भारतीय पैट्रोलियम संस्थान का देश के विकास में है विशेष योगदानः डॉ. हरेन्द्र सिंह बिष्ट

पलायन पर लगाम के लिए धामी सरकार की नई पहल

दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 31 | मूल्य 05 रुपये | 21-27 दिसंबर, 2025

'जी-राम-जी' बिल पर विपक्ष आग-बबूला

वर्ष 15 | अंक 31

दिव्य हिमगिरि

21-27 दिसंबर, 2025

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा सरस्वती प्रेस, 2, ग्रीन पार्क, निरंजनपुर, देहरादून से मुद्रित तथा 39/7 ई, ई. सी. रोड, (निकट मार्शल स्कूल सीनियर विंग) देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*
*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

संपादकीय

धुंध का बढ़ता संकट

गहराते प्रदूषण संकट के बीच ठंड बढ़ने के साथ ही कोहरे की मार पड़ने लगी है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर आए दिन गाड़ियों के टकराने की खबरें आ रही हैं। मंगलवार को धुंध के कारण यमुना एक्सप्रेसवे पर आगरा से नोएडा के बीच सात बसों और तीन गाड़ियों के टकराने एवं कई अन्य शहरों में भी इसी तरह की दुर्घटनाओं में 24 लोगों की जान जाने के बाद यह बहस तेज हो गई है कि जवाबदेही कौन लेगा और कैसे रोकथाम के लिए कोई रास्ता निकलेगा। अभी तक तो प्रदूषण एवं धुंध के कारण बढ़ते संकट के बीच राजनीतिक बयानबाजी भर सामने आती रही है और जिम्मेदारी से बचने की कोशिश में सत्ता प्रतिष्ठान एवं प्रशासन दिखा है। हालात ये हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों का कोई असर नहीं पड़ रहा है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण की समस्या धीरे-धीरे गंभीर होती है और धुंध बढ़ने के साथ राजमार्गों पर दुर्घटनाएं बढ़ने लगती हैं। राजमार्गों पर धुंध के बीच रफ्तार पर लगाम को लेकर न कोई चेतावनी है, न कोई अंकुश। दरअसल, प्रदूषण का गहराता संकट मौसम की मार तो है ही, सरकार की अनदेखी और लापरवाही से समस्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। इस तरह की दिक्कतों को लेकर चर्चा होती है, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए जाते। हाल में खबर आई कि दिल्ली दुनिया की सर्वाधिक प्रदूषित राजधानी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश के सर्वाधिक प्रदूषित 32 शहरों में ग्यारह हरियाणा के पाए गए। स्पष्ट है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में धुएं की परत के आगे बेबसी है। सरकारी स्तर पर कवायद घोषणाओं और आरोप-प्रत्यारोप तक सीमित दिखती है। यही वजह है कि पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को फटकार लगाई कि प्रदूषण रोकने के लिए जमीनी स्तर पर प्रयास न के बराबर हैं। दरअसल, हर साल ठंड शुरू होते ही हवा की दशा-दिशा में बदलाव के साथ ही आसमान में धुएं की परत जमने लगती है। यही वजह है कि पराली संकट व अन्य कारणों से बढ़ते प्रदूषण से चिंतित सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। हालत यह है कि बहुत सारे लोगों के सामने सांस से संबंधित परेशानियों सहित कई तरह की मुश्किलें पैदा हो रही हैं, लेकिन अब भी प्रदूषण को कम या दूर करने के लिए कोई ईमानदार इच्छाशक्ति नहीं दिखती। किसानों के मुद्दों को जोर-शोर से उठाकर श्रेय लेने वाले राजनेताओं की जवाबदेही तय होनी चाहिए। बंपर पैदावार का श्रेय लेने वाले नेता तब कहां चले जाते हैं, जब पराली जलाने का संकट पैदा होता है? यह भी हकीकत है कि प्रदूषण संकट के मूल में सिर्फ पराली समस्या ही नहीं है। हमारी उपभोक्ता संस्कृति, वाहनों का अंबार, सार्वजनिक यातायात सुविधा का पर्याप्त न होना, अनियोजित निर्माण कार्य, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग तथा कूड़े का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण न होना भी प्रदूषण संकट के मूल में है। शासन को भी आग लगने पर कुआं खोदने की मानसिकता से बचना होगा और दूरगामी प्रभावों वाली नीतियां लागू करनी होंगी। जवाबदेही तय होनी चाहिए। ऐसा पहली बार हुआ है शनिवार को देहरादून घाटी भी पूरे दिन के लिए धुंध के आगोश में चली गई। जो शहर सर्दियों में खिली धूप के लिए जाना जाता था, वहां कोहरे की सफेद चादर थी। देहरादून जैसे साफ स्वच्छ वातावरण वाले शहर का एक्यूआई भी 200 के पार चला गया है। हालात यही रहे तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा पहाड़ मैदान की तरह कोहरे के आगोश में होगा, तब प्रधानमंत्री की यहां आकर घाम तापने वाली अपील का क्या होगा।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

दुनियाभर में बढ़ रही है ध्यान योग की स्वीकार्यता!

डॉ श्रीगोपाल नारसन
एडवोकेट

पतंजलि के योगसूत्र से लेकर गीता के उपदेश तक हर जगह ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। अभी तक कुछ लोग योग आसनों को ही ध्यान समझते रहे हैं, लेकिन देश दुनिया मे राजयोग के माध्यम से स्वयं को देहभान से परे कर आत्मस्वरूप में रहकर परमात्मा के प्रति ध्यान लगाने की विधि को ब्रह्माकुमारीज संस्था ने ही पहुंचाया है। शारिरिक आसन के द्वारा हम अपने शरीर को मजबूत करने के साथ ही रोग मुक्त बना सकते हैं, ताकि ध्यान लगाकर हम एक साथ तन-मन को लाभ पहुंचा सकते है। हमारा शरीर एक जगह पर स्थिर हो और ध्यान की प्रक्रिया आसानी से हो सके इसके लिए श्रीमद् भगवद् गीता में ध्यान को लेकर महत्वपूर्ण बातें बताई गई हैं, और साथ ही इससे होने वाले लाभ का भी गीता में उल्लेख किया गया है।

भगवद् गीता में ध्यान को एक योगक्रिया माना गया है। जो आपको आत्म अनुशासन की ओर ले जाता है। निरंतर इसका अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ती है, तनाव से मुक्ति मिलती है। मानसिक स्थिरता और संतुलन भी ध्यान करने से प्राप्त होता है। विकारों से मुक्ति पाने और मन की निर्मलता के लिए भी ध्यान किया जाता है। ध्यान जब गहन होने लगता है तो व्यक्ति को समाधि की प्राप्त होने लगती है। ध्यान के जरिए आत्मा का परमात्मा से मिलन ही ब्रह्माकुमारीज का राजयोग है। यानि ध्यान वह योग प्रक्रिया है जिसके जरिये हम स्वयं पर सिद्धि प्राप्त करते हैं। ध्यान करने वाले व्यक्ति का मन नियंत्रित रहता है और वो वर्तमान में जीता है। मानसिक और शारीरिक स्थिरता को ही ध्यान कहा जा जाता है।

गीता के पंचम और षष्ठम अध्याय में योग करने की सही विधि की जानकारी हमको मिलती है। श्रीकृष्ण ने परमात्म निमित्त बन अर्जुन को महाभारत के युद्ध के समय बताया है कि, कैसे मन और इंद्रियों को वश में करने के लिए ध्यान क्रिया की जानी चाहिए।

गीता के अनुसार, ध्यान करने के लिए सबसे पहले किसी शुद्ध स्थान पर आसन बिछाकर बैठना चाहिए। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि, ना ही स्थान बहुत ऊंचा हो और ना ही बहुत नीचे। आसन पर बैठने के बाद अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए और इंद्रियों और मन को नियंत्रिण में लाने का अभ्यास करना चाहिए।

ध्यान करने के लिए सिर व गले को समान और अचल रखते हुए सुखासन में योगी को बैठना चाहिए। बाहरी चीजों से ध्यान को हटाकर नासिका के अग्र भाग यानि दोनों भौहों के बीच जहां आत्मा निवास करती है, के प्रति ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तत्पश्चात सभी प्रकार के विषयों से मन को हटाकर नेत्रों को भृकुटी के मध्य में स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। इसके बाद प्राण और अपान वायु को सम करना चाहिए।

इसके बाद मन के सभी विकारों से दूर होकर, उत्तेजनारहित और शांति के साथ ध्यान और ईश्वर के चिंतन में बैठे रहना चाहिए। इस तरह से निर्मल और निर्विकार व्यक्ति परमतत्व का ध्यान करते हुए आनंद की अंतिम सीमा को प्राप्त करता है और उसे शांति मिलती है। गीता के अनुसार, ध्यान उसका ही सिद्ध होता है, जो न अधिक खाता है और ना ही अधिक भूखा रहता है। अधिक जगाने या सोने वाले को भी ध्यान की सिद्धि प्राप्त नहीं होती। सुख में अत्यधिक खुश और दुख में ज्यादा दुखी होने वाला व्यक्ति भी ध्यान को सिद्ध नहीं कर पाता। गीता में बताया गया है कि, जो व्यक्ति उचित आहार-विहार करता है, उसी को ध्यान-योग में सिद्धि प्राप्त होती है।

गीता में बताई गई इन शिक्षाओं को जीवन में आजमाकर हम ध्यान कर सकते हैं और मानसिक शांति पा सकते हैं। ध्यान करने से हमको न केवल मानसिक शक्ति मिलती है, बल्कि अपने लक्ष्यों को भी हम पा सकते हैं। ध्यान हमारी एकाग्रता को बढ़ाता है और हम अपना शतप्रतिशत अपने लक्ष्य को दे पाते हैं। इसके साथ ही एक आदर्श और व्यवस्थित समाज भी ध्यान के जरिए हम स्थापित कर सकते हैं। ध्यान मानसिक और शारीरिक विकारों को दूर करता है, यानि स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी ध्यान करना अति आवश्यक है। इस वर्ष विश्व ध्यान दिवस की थीम ''आंतरिक शांति, वैश्विक सद्भाव'' है। पतंजलि के योगसूत्र से लेकर गीता के उपदेश तक हर जगह ध्यान को बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में कोर समूह के अन्य देशों के साथ मिल कर भारत ने 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया है।वास्तव में ध्यान मानसिक तथा शारीरिक विकारों को दूर करने में कारगर होने के साथ ही यह स्वस्थ जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है।विश्व ध्यान दिवस को एक अंतरराष्ट्रीय उत्सव भी हम कह सकते है, जिसमें शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक कल्याण के लिए ध्यान का अभ्यास करने का संकल्प लिया गया है।भारत के साथ श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको, लिकटेंस्टीन और अंडोरा जैसे 193 सदस्यीय देशो ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में शविश्व ध्यान दिवसश के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित करने में अहम भूमिका निभाई। जिसे आत्मसात करने के लिए 140 देशो की अंतरराष्ट्रीय आध्यात्मिक संस्था ब्रह्माकुमारीज ने एक सार्थक पहल की है। ब्रह्माकुमारीज का उद्देश्य दुनिया मे शांति को बहाल करना है। इसके लिए, यह संस्था लोगों को सहज राजयोग की विधि सिखाती है। साथ ही ब्रह्माकुमारीज के जरिए लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान भी दिया जाता है। इसी ईश्वरीय ज्ञान के जरिए युग परिवर्तन होना अवश्यसम्भावी है।

'जी-राम-जी' बिल पर विपक्ष आग-बबूला

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

संसद के शीतकालीन सत्र के समापन पर अचानक उठे विवाद ने पूरे देश की राजनीति में सियासी भूचाल मचा दिया। मोदी सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-जी रामजी बिल, 2025' पेश किया और पारित कर दिया, जिसमें महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। इस फैसले के तुरंत बाद कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने इसे महात्मा गांधी का अपमान करार देते हुए हंगामा खड़ा कर दिया और संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। केंद्र सरकार ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मनरेगा का मूल नाम 'नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट' (नरेगा) था और 2009 में राजनीतिक लाभ के कारण गांधी का नाम जोड़ा गया था। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार ने महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवित रखा है और बिल का उद्देश्य सिर्फ योजना का नाम आधुनिक भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप बदलना है। विपक्ष ने इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति पर सवाल उठाए, जिसमें उन्होंने कहा कि सरकार आधुनिक भारत के प्रतीकों और उनके इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रही है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अब अंत में महात्मा गांधी के नाम से खिलवाड़ करके इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकसित भारत-जी रामजी बिल पर कहा- संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा है लेकिन आप आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आते हैं और उसके लिए कम समय रखते हैं। उसे हड़बड़ी में पास करते हैं। ये अपने आप में संदिग्ध बात है। वहीं राहुल गांधी ने कहा- मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए। बिल बिना ठीक से जांच-पड़ताल के संसद में पास कर दिया गया।

संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिनों में देश की राजनीति में अचानक सियासी भूचाल मच गया। मोदी सरकार ने मनरेगा योजना का नाम बदलकर 'विकसित भारत-जी रामजी बिल, 2025' प्रस्तुत किया और इसे पारित कर दिया। बिल में महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने के फैसले के बाद विपक्षी दलों ने संसद परिसर में जोरदार हंगामा किया और संविधान सदन के बाहर धरने पर बैठ गए। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैरमौजूदगी के बीच बिल ध्वनिमत से पास कर दिया गया।

यह विवाद न केवल संसद में गरमाया बल्कि पूरे देश में राजनीतिक बहस का केंद्र बन गया। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि मनरेगा का मूल नाम 'नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट' (नरेगा) था। उन्होंने स्पष्ट किया कि 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ के लिए गांधी का नाम योजना में जोड़ दिया था। उन्होंने कहा, 'हमने महात्मा गांधी के आदर्शों को जीवित रखा है। योजना का नाम बदलना सिर्फ आधुनिक भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप किया गया है। यह किसी का अपमान नहीं है।' विपक्षी दलों ने बिल पारित होने के बाद इसे महात्मा गांधी का अपमान करार देते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, 'सत्र की शुरुआत रवींद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत में महात्मा गांधी के नाम से खिलवाड़ करके

इतिहास को बदलने का प्रयास किया जा रहा है। सरकार ने तीन आधुनिक भारत निर्माणकर्ताओं टैगोर, गांधी और जवाहरलाल नेहरू के योगदान को नकारने की नीति अपनाई है। यह इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का प्रयास है।' संसद में वंदे मातरम् पर हुई बहस भी इसी विवाद के बीच छिड़ी। जयराम रमेश ने कहा कि 1937 में टैगोर की सिफारिश पर ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया था कि वंदे मातरम् के पहले दो छंदों को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार की रणनीति इस देश के महान नेताओं के योगदान को कमतर दिखाने और उन्हें बदनाम करने की रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि मैं अपनी मां की और भारत मां की कसम खाकर कहता हूं कि ये बिल गरीबों की भलाई के लिए नहीं है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने विकसित भारत-जी रामजी बिल पर कहा- संसद का सत्र इतने दिनों से चल रहा है लेकिन आप आखिरी दिनों में कुछ बिल लेकर आते हैं और उसके लिए कम समय रखते हैं। उसे हड़बड़ी में पास करते हैं। ये अपने आप में संदिग्ध बात है। उन्होंने कहा- प्रदूषण पर चर्चा क्यों नहीं हो सकती? चर्चा होनी चाहिए, सबकी बात सुननी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा- मोदी सरकार ने एक दिन में मनरेगा के 20 साल खत्म कर दिए। बिल बिना ठीक से जांच-पड़ताल के संसद में पास कर दिया गया। मोदी के लक्ष्य साफ है। ग्रामीण भारत, खासकर पिछड़े वर्गों की ताकत को कमजोर करना, सत्ता को केंद्रीकृत करना और फिर सुधार के नाम पर नारे बेचना। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मनरेगा योजना से गांधी का नाम हटाना गलत संदेश देता है। यह गरीब और मजदूरों की कल्याण योजना के मूल उद्देश्य को कमजोर करने की कोशिश है। विपक्ष के हंगामे के बाद, केंद्र सरकार ने अपने तर्क पेश किए। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत-जी रामजी बिल का उद्देश्य देश को आधुनिक भारत

रोजगार की गारंटी 'मनरेगा' कानून खत्म, अब काम देने की बाध्यता समाप्तः *यशपाल आर्य*

यशपाल आर्य, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट का नाम बदलकर विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) रख दिया गया है। नया कानून (VB&G RAM G) मनरेगा के "काम के अधिकार" के मूल सिद्धांत को कमजोर कर रहा है।

उन्होंने कहा कि मनरेगा से सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम नहीं हटाया गया है, इसके अलावा भी कई परिवर्तन अत्यंत चिंताजनक है। पहले इस योजना में केंद्र सरकार का अंशदान 90 प्रतिशत और 10 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का था। मनरेगा अकुशल उद्यमियों के लिए स्कीम थी, जिसका बजट केंद्र सरकार के पास था, लेकिन अब सिर्फ 60 प्रतिशत अंशदान केंद्र का होगा और 40 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होगा।

श्री आर्य ने कहा कि मनरेगा मांग पर आधारित एक स्कीम थी, अगर कोई मजदूर काम मांगता था, तो केंद्र को उसे काम देकर उसका भुगतान करना पड़ता था, नई स्कीम में डिमांड के आधार पर काम नहीं मिलेगा। अब काम केंद्र के पूर्व-निर्धारित मानक और बजट आवंटन के आधार पर ही मिलेगा। फंड खत्म, तो अधिकार खत्म। अगर फंड से ज्यादा काम दिया तो उसका भुगतान राज्य सरकार को करना होगा। उन्होंने कहा कि रोजगार की लीगल गारंटी स्कीम को बदलकर, अब केंद्र द्वारा संचालित प्रचार योजना में बदल दिया गया है, जिसमें खर्च राज्य करेंगे। मनरेगा में काम ग्राम सभाओं और पंचायतों के जरिए होता था, जो स्थानीय जरूरतों के आधार पर काम की योजना बनाती थीं। इससे लोकतंत्र की पहली कड़ी पंचायतों को और भी मजबूती मिलती थी।

श्री आर्य ने कहा कि नई स्कीम में जीआईएस उपकरण, पीएम गति शक् और केंद्र के डिजिटल नेटवर्क अनिवार्य हैं। स्थानीय प्राथमिकताएं अब विकसित भारत नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैक से फिल्टर होंगी। इसमें बायोमेट्रिक्स, जियो-टैगिंग, डैशबोर्ड्स और ऑडिट जरूरी है। साफ है, वह लाखों ग्रामीण मजदूर जो इतनी तकनीक नहीं समझते हैं, वो काम से वंचित रह जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही किसी राज्य को कितना बजट मिलेगा, ये केंद्र सरकार तय करेगी। इसके मानक होंगे, लेकनि हम जानते हैं इस मामले में विपक्ष की सरकारों को क्या मिलेगा और किस आधार पर मिलेगा यह तय किया जायेगा। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मजदूरों को खेती किसानी के सीजन में दो महीने काम नहीं मिलेगा। रोजगार गारंटी का ये एक्ट दो महीने तक रोजगार की कोई गारंटी नहीं देगा। मतलब मजदूर को उसके भाग्य के भरोसे छोड़ दिया गया। अब उन्हें काम देने वाला थोड़े से अनाज पर काम करवाए या किसी और तरह से शोषण करे, सरकार को फर्क नहीं पड़ता। किसी योजना का नाम बदलना सिर्फ कागजी बदलाव नहीं होता-इस पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपये खर्च होते हैं, जिनका सीधा बोझ जनता पर पड़ता है।

उन्होंने कहा कि असली सवाल यह है कि क्या नाम बदलने से गाँव के मजदूर की जिंदगी बदलेगी? क्या इससे बेरोजगारी या महंगाई कम होगी? यह बदलाव तो मनरेगा की रोजगार गारंटी की आत्मा पर सीधा हमला है। फंड घटाना, मांग आधारित काम खत्म करना और राज्यों पर बोझ डालना, सब मिलकर मजदूर को असुरक्षित बना देता है।

श्री आर्य ने कहा कि देश में गरीबी खत्म करने की दिशा में एक भी काम नहीं हो रहा है, गरीबों को खत्म करने के लिए सबकुछ हो रहा है। धन का केंद्रीय करण कर सिर्फ 10 प्रतिशत लोगों की आय के आधार पर 90 प्रतिशत लोगों को विकसित भारत का सपना दिखाकर मूर्ख बनाया जा रहा है। जब देश की जनता रोजगार और राहत की उम्मीद कर रही है, तब सरकार को प्रतीकों की राजनीति छोड़कर जमीनी हकीकत पर काम करना चाहिए। श्री यशपाल आर्य ने कहा कि ऐसे प्रावधान का कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। करोड़ों गरीब, मजदूरों और कामगारों के हकों को हम सत्ता के हाथों छिनने नहीं देंगें।

की दिशा में ले जाना है। बिल में कोई भी नेता या इतिहास का अपमान नहीं है। यह सिर्फ योजना के नाम और दृष्टिकोण को आधुनिक बनाना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल योजना का नाम बदलना था, न कि किसी का अपमान करना। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर 'विकसित भारत-जी रामजी बिल' किया गया है ताकि यह योजना ग्रामीण रोजगार और विकास की दिशा में आधुनिक दृष्टिकोण को दर्शा सके। उन्होंने कहा, यह बिल ग्रामीण भारत की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए लाया गया है।

केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में आठ विधेयक पास कराए

संसद का शीतकालीन सत्र शुक्रवार को खत्म हो गया। शीतकालीन सत्र में 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक कुल 14 बिल लाने का लक्ष्य रखा गया था। हालांकि, लगातार विपक्ष और सरकार के बीच बहस और आरोप-प्रत्यारोप के बीच केवल 8 बिल पास हो सके। दो बिलों को कमेटी में भेजा गया और कुछ बिल पेश ही नहीं किए गए। इनमें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) की जगह लेने के लिए लाया गया 'विकसित भारत-जी राम जी विधेयक, 2025' शामिल है जिसे लेकर विपक्ष ने भारी विरोध दर्ज कराया। सदन ने 'भारत के रुपांतरण के लिए नाभिकीय ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्द्धन (शांति) विधेयक, 2025', 'सबका बीमा सबकी रक्षा (बीमा कानूनों में संशोधन) विधेयक, 2025' और वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगें-प्रथम बैच और संबंधित विनियोग (संख्याक 4) विधेयक, 2025 को भी पारित किया। देश में अप्रचलित एवं पुराने हो चुके 71 कानूनों को निरस्त और संशोधित करने के प्रस्ताव वाले 'निरसन और संशोधन विधेयक, 2025' को भी निम्न सदन की स्वीकृति प्राप्त हुई। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने के विषय पर चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण से हुई। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत एक दिसंबर को हुई थी। इस सत्र में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो एयरलाइन्स के परिचालन में व्यवधान के मुद्दे पर सदन में वक्तव्य दिया। लोकसभा ने विश्वविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षण संस्थानों को स्वतंत्र स्व-शासन वाले संस्थान बनाने के उद्देश्य से लाए गए 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक, 2025' को संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने को मंजूरी दी। इस बीच, विकसित भारत-जी रामजी बिल पारित होना सत्र का सबसे विवादित और चर्चित मुद्दा बन गया। विपक्ष ने बिल पारित होने के बाद कहा कि मोदी सरकार इस सत्र के दौरान महात्मा गांधी और अन्य आधुनिक भारत के निर्माण ाकर्ताओं के योगदान को नजरअंदाज कर रही है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, यह केवल नाम बदलने का मामला नहीं है। यह हमारे देश के इतिहास और पहचान के साथ खिलवाड़ है। सरकार ने इस बिल के जरिए राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की है। विपक्ष ने संसद परिसर के बाहर धरने के दौरान जोर देकर कहा कि वे इस बिल के खिलाफ सभी संवैधानिक और लोकतांत्रिक उपाय अपनाएंगे। वहीं, भाजपा के नेताओं ने विपक्ष के हंगामे को राजनीतिक तौर पर औचित्यहीन बताया। उन्होंने कहा कि इस बिल का उद्देश्य केवल योजना की आधुनिक और विकास-केंद्रित दिशा को दर्शाना है। मनरेगा योजना, जो देश में ग्रामीण रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण योजना रही है, उसके नाम में बदलाव और गांधी का नाम हटाना राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन गया है। भाजपा नेताओं का कहना है कि इससे योजना की कार्यक्षमता और ग्रामीण रोजगार की दिशा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके विपरीत, विपक्ष इसे देश की राजनीति और इतिहास के साथ खिलवाड़ मान रहा है। सत्र के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौकों पर कहा कि उनका उद्देश्य देश को आधुनिक और विकसित भारत की दिशा में ले जाना है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि बिल का मकसद सिर्फ योजना का नाम बदलकर इसे विकास और रोजगार के नजरिए से और अधिक सार्थक बनाना है। विपक्ष इसे न केवल महात्मा गांधी के अपमान के रूप में देख रहा है, बल्कि इसे मोदी सरकार की 'इतिहास बदलने की कोशिश' के रूप में भी प्रचारित करने की रणनीति बना रहा है। कुल मिलाकर, शीतकालीन सत्र ने राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, विकसित भारत-जी रामजी बिल का पारित होना, विपक्ष का जोरदार विरोध, गांधी नाम विवाद और धरने प्रदर्शन ने संसद और देश की राजनीति में नए सियासी भूचाल को जन्म दे दिया है।

ग्रामीण भारत की आजीविका की मजबूत रीढ़ है मनरेगा

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) देश की सबसे बड़ी और महत्वाकांक्षी सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है। इसकी शुरुआत वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस कानून के तहत हर ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का मजदूरी आधारित रोजगार देने की कानूनी गारंटी दी गई है। मनरेगा के तहत काम मांगने वाले वयस्क सदस्य को 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। यदि तय समय सीमा में काम नहीं दिया जाता, तो संबंधित लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। योजना का मुख्य उद्देश्य केवल रोजगार देना ही नहीं, बल्कि ग्रामीण इलाकों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण करना भी है, जिससे गांवों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। इस योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, तालाब निर्माण, खेत तालाब, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, सिंचाई नहरों की खुदाई, भूमि सुधार और ग्रामीण बुनियादी ढांचे से जुड़े कार्य कराए जाते हैं। इससे न सिर्फ लोगों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलता है, बल्कि गांवों की उत्पादन क्षमता और पर्यावरण संतुलन भी बेहतर होता है। मनरेगा की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें महिलाओं की भागीदारी को विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया है। कानून के अनुसार कम से कम एक-तिहाई रोजगार महिलाओं को दिया जाना अनिवार्य है। साथ ही मजदूरी का भुगतान सीधे बैंक खाते में किया जाता है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगता है। ग्रामीण पलायन रोकने में भी मनरेगा की अहम भूमिका मानी जाती है। गांव में ही काम मिलने से लोगों को शहरों की ओर मजबूरी में जाने से राहत मिलती है। यही कारण है कि मनरेगा को ग्रामीण भारत की आर्थिक सुरक्षा की ढाल और सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जाता है। समय-समय पर बजट आवंटन, मजदूरी दर और काम के स्वरूप को लेकर इस योजना पर राजनीतिक बहस भी होती रही है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि मनरेगा ने देश के करोड़ों ग्रामीण परिवारों के जीवन में स्थिरता और सम्मानजनक रोजगार का रास्ता खोला है। फिलहाल केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलने संबंधी विधेयक सांसद के दोनों सदनों में पारित करा लिया है। अब इस योजना का नाम 'विकसित भारत-जी रामजी' होगा।

पलायन पर लगाम के लिए धामी सरकार की नई पहल

उत्तराखंड में लगातार बढ़ रही पलायन की समस्या से निपटने के लिए धामी सरकार ने एक अहम और व्यावहारिक पहल शुरू करने का फैसला लिया है। राज्य सरकार ने प्रवासी पंचायतों के आयोजन का निर्णय लिया है, जिसके जरिए राज्य से बाहर रह रहे उत्तराखंडियों को अपने गांवों और मूल क्षेत्रों से दोबारा जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इन पंचायतों के माध्यम से प्रवासियों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार, स्वरोजगार और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, ताकि वे गांव वापसी के लिए प्रेरित हो सकें। इन पंचायतों में प्रवासी उत्तराखंडियों को स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, बागवानी, स्टार्टअप, होम-स्टे और कुटीर उद्योग से जुड़ी संभावनाओं से अवगत कराया जाएगा। साथ ही उनकी समस्याएं, सुझाव और अपेक्षाएं भी सीधे सरकार तक पहुंचेंगी, ताकि नीतियों को जमीनी जरूरतों के अनुरूप ढाला जा सके। सरकार का लक्ष्य है कि गांवों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ें, रोजगार के नए अवसर पैदा हों और उत्तराखंड का युवा वर्ग अपने ही राज्य में सुरक्षित और सम्मानजनक भविष्य देख सके। शंभू नाथ गौतम।

उत्तराखंड में लंबे समय से जारी पलायन की समस्या को रोकने और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए धामी सरकार ने एक नई और दूरगामी पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने प्रवासी पंचायतों के आयोजन का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य राज्य से बाहर काम करने वाले उत्तराखंडियों को उनके गांवों और मूल क्षेत्रों से जोड़ना है। इस पहल के तहत सरकार प्रवासियों को स्थानीय रोजगार, स्वरोजगार, पर्यटन, कृषि, होम-स्टे, कुटीर उद्योग और अन्य संभावित अवसरों से अवगत कराएगी, ताकि वे अपने गाँव लौटकर स्थायी रूप से रोजगार प्राप्त कर सकें और राज्य के विकास में योगदान दे सकें। धामी सरकार का मानना है कि उत्तराखंड जैसे भौगोलिक रूप से संवेदनशील और पर्वतीय राज्य में पलायन केवल रोजगार का मुद्दा नहीं है, बल्कि यह सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे को भी प्रभावित करता है। पिछले कई वर्षों में युवा वर्ग बड़े शहरों और दूसरे राज्यों की ओर पलायन कर रहा है, जिससे पहाड़ी और ग्रामीण इलाके धीरे-धीरे खाली हो रहे हैं। इससे कृषि, स्थानीय कुटीर उद्योग, पर्यटन और पारंपरिक आजीविका पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। प्रवासी पंचायतों की पहल इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने के लिए तैयार की गई रणनीति का हिस्सा है।

इन पंचायतों के आयोजन में सरकार स्थानीय प्रतिनिधियों, पंचायतों के अधिकारियों और विकास एजेंसियों को भी शामिल करेगी, ताकि प्रवासियों की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को सीधे सरकार तक पहुंचाया जा सके। इससे नीतियों और योजनाओं को जमीनी हकीकत के अनुसार तैयार करना

सीएम धामी ने प्रवासी पंचायतों और रिवर्स पलायन को गति देने के दिए निर्देश

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार, 19 दिसंबर को शासकीय आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की 10वीं बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि पलायन राज्य के लिए बड़ी चुनौती रही है, लेकिन पिछले चार-पांच वर्षों में पलायन को रोकने और लोगों को अपने गांव लौटने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका बढ़ाने हेतु कई योजनाएं लागू की गई हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को ऋण लेने पर अनुदान भी प्रदान किया जा रहा है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिल रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य भर में प्रवासी पंचायतों का आयोजन किया जाए, जिसमें देश और विदेश में कार्यरत प्रवासियों को आमंत्रित किया जाए। उन्हें राज्य सरकार की पलायन रोकने और गांव वापसी से जुड़ी पहलों की जानकारी दी जाए और उनके सुझाव भी लिए जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आयोग के सदस्यों को अन्य राज्यों में जाकर पलायन रोकने और गांव वापसी को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी देने और इस क्षेत्र में किए गए नवाचारों का अध्ययन करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि त्रियुगीनारायण की तर्ज पर राज्य के 25 नए स्थलों को विवाह स्थल के रूप में विकसित किया जाए। इन स्थलों में सभी मूलभूत सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जाएगा। आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एसएस नेगी ने बताया कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में अब गांव वापसी का रुझान देखने को मिल रहा है। अब तक 6,282 व्यक्ति अपने गांव लौट चुके हैं, जिनमें देश और विदेश से लौटे लोग शामिल हैं। अधिकतर लोग पर्यटन और छोटे उद्योग के क्षेत्र में कार्यरत हैं और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

बैठक में आयोग के सदस्यों ने गांव वापसी को और गति देने के लिए कई रचनात्मक सुझाव प्रस्तुत किए। इस अवसर पर सचिव विनय शंकर पाण्डेय, धीराज गर्ब्याल, डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, सी. रविशंकर, अपर सचिव अनुराधा पाल, डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, चन्द्र सिंह धर्मशक्तू, संतोष बडोनी, सुरेश जोशी, आयोग के सदस्य अनिल सिंह शाही, दिनेश रावत, सुरेश सुयाल, राम प्रकाश पैन्यूली और रंजना रावत उपस्थित रहे।

आसान होगा। इसके अलावा, प्रवासी पंचायतों में रोजगार और स्वरोजगार से जुड़े व्यावहारिक प्रशिक्षण और मार्गदर्शन भी दिया जाएगा, जिससे युवाओं को अपने गांवों में ही आर्थिक रूप से सक्षम बनने के अवसर मिलेंगे। सरकार ने यह पहल ऐसे समय में की है, जब पर्यटन, कृषि और स्थानीय उद्योग के क्षेत्र में नई संभावनाएं उभर रही हैं। पर्यटन स्थलों पर होम-स्टे, गेस्ट हाउस और छोटे व्यवसाय के अवसर बढ़ रहे हैं। कृषि और बागवानी के क्षेत्र में भी नई तकनीक और निवेश के अवसर उपलब्ध हैं। प्रवासी पंचायतों के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि बाहरी राज्यों में काम कर रहे लोग इन अवसरों की जानकारी प्राप्त करें और उन्हें अपने गांव में अपनाकर रोजगार और आय के नए स्रोत विकसित करें। इस पहल से ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। प्रवासी पंचायतों के माध्यम से लौटे हुए युवा न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भागीदारी करेंगे। इससे गांवों की सामाजिक संरचना और परंपरागत जीवनशैली को बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार का कहना है कि प्रवासी पंचायतों की सफलता के लिए व्यापक जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। इसमें सोशल मीडिया, स्थानीय मीडिया, पंचायत बैठकों और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से प्रवासियों को कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा, राज्य सरकार विभिन्न विभागों के सहयोग से रोजगार, प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता से संबंधित विशेष योजनाओं की भी जानकारी प्रवासियों तक पहुंचाएगी। इस तरह, प्रवासी पंचायतें केवल संवाद का मंच नहीं, बल्कि रोजगार और विकास के अवसरों से सीधे जोड़ने का एक मजबूत माध्यम साबित होंगी।

पलायन रोकने की इस पहल से युवा वर्ग को अपने गांवों में स्थायी रोजगार और विकास के अवसर मिलेंगे। यह कदम राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ-साथ ग्रामीण और पर्वतीय इलाकों के लोगों की जीवन गुणवत्ता को भी बेहतर बनाएगा। धामी सरकार का यह उद्देश्य स्पष्ट है कि गांवों को खाली होने से बचाया जाए और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के अवसर बढ़ें। सरकार ने यह भी संकेत दिया है कि भविष्य में प्रवासी पंचायतों की संख्या बढ़ाई जाएगी और इसे हर जिले में लागू किया जाएगा। पंचायतों में लौटे हुए प्रवासियों को स्थानीय संसाधनों, सरकारी योजनाओं और निवेश के अवसरों से जोड़कर उन्हें स्थायी रूप से गांव में रोजगार देने के लिए विशेष मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, राज्य सरकार उन युवाओं के लिए विशेष स्कीम तैयार कर रही है, जो शहरों और बाहरी राज्यों में काम कर रहे हैं, ताकि उन्हें गांव लौटकर स्वरोजगार और स्थानीय उद्योग में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। धामी सरकार का यह कदम राज्य के आर्थिक विकास और सामाजिक स्थिरता के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। प्रवासी पंचायतों की मदद से न केवल गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, बल्कि युवा वर्ग के बीच स्थानीय संसाधनों के उपयोग और विकास की भावना भी जागृत होगी। इस पहल से राज्य में पलायन की दर में कमी आने, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने और युवाओं को उनके ही राज्य में स्थायी अवसर देने की उम्मीद जताई जा रही है।

धामी सरकार ने सड़क-रोपवे-स्वास्थ्य परियोजनाओं को दी हरी झंडी

उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे को नई मजबूती देने की दिशा में धामी सरकार ने एक साथ कई बड़े और अहम फैसले लिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने राज्य राजमार्गों पर 235 पुलों के अपग्रेड और सुदृढ़ीकरण के साथ-साथ सड़क, रोपवे, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और शहरी विकास से जुड़ी अनेक परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 183.97 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की। जिससे प्रदेश की कनेक्टिविटी, सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक सुविधओं में व्यापक सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। धामी सरकार का फोकस खास तौर पर पर्वतीय और दुर्गम इलाकों में सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने पर है। राज्य के कई पुल पुराने और संकरे होने के कारण भारी वाहनों, आपातकालीन सेवाओं के लिए चुनौती बने हुए थे, जिन्हें अब आधुनिक तकनीक से अपग्रेड किया जाएगा। इससे चारधाम यात्रा, सीमावर्ती क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों तक आवाजाही आसान होने के साथ-साथ दुर्घटनाओं पर भी प्रभावी नियंत्रण संभव होगा। इसके साथ ही मसूरी और रानीबाग-नैनीताल मार्ग पर रोपवे परियोजनाओं के फिजिबिलिटी अध्ययन, यमुनोत्री क्षेत्र में सड़क और हेलीपैड निर्माण, मेडिकल कॉलेजों के विस्तार, आवासीय और शहरी विकास योजनाओं को मंजूरी देकर सरकार ने साफ संकेत दिया है कि उत्तराखंड में विकास को बहुआयामी गति दी जा रही है। धमी सरकार के ये फैसले राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और भविष्य की जरूरतों के अनुरूप उत्तराखंड को तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

उत्तराखंड में विकास की दिशा को नई गति देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व वाली सरकार ने एक साथ कई बड़े और दूरगामी फैसले लिए, जिनका सीधा असर राज्य की सड़क सुरक्षा, कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सेवाओं, पर्यटन, शिक्षा और शहरी सुविधओं पर पड़ने वाला है। धामी सरकार ने जहां राज्य राजमार्गों पर स्थित 235 पुलों के अपग्रेड और सुदृढ़ीकरण को मंजूरी देकर सड़क ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है, वहीं सड़क, रोपवे, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा और आधरभूत संरचना से जुड़ी अनेक परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि भी स्वीकृत की है। सरकार के इन फैसलों को उत्तराखंड के समग्र विकास की दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य पर्वतीय

भूगोल, आपदाओं की चुनौती और बढ़ती यातायात जरूरतों के दौर से गुजर रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धमी ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड जैसे संवेदनशील और भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण राज्य में सड़कें और पुल केवल यातायात के साधन नहीं हैं, बल्कि वे जीवनरेखा की तरह हैं। राज्य के कई हिस्सों में मौजूद पुल वर्षों पुराने हैं, जो वर्तमान यातायात दबाव, भारी वाहनों और आपातकालीन सेवाओं की जरूरतों के अनुरूप नहीं रह गए थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य राजमार्गों पर 235 पुलों के अपग्रेडेशन का फैसला लिया है। इन पुलों को आधुनिक मानकों के अनुसार मजबूत किया जाएगा, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने, भारी वाहनों की सुरक्षित आवाजाही और आपदा के समय राहत व बचाव कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। यह निर्णय चारधम यात्रा मार्गों, सीमावर्ती क्षेत्रों और दूरस्थ ग्रामीण इलाकों के लिए भी राहत भरा माना जा रहा है। धमी सरकार का मानना है कि पुलों और सड़कों की मजबूती से न केवल आम लोगों की रोजमर्रा की आवाजाही आसान होगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। पर्यटन, कृषि, उद्योग और व्यापार सीधे तौर पर बेहतर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं। खासकर चारधम यात्रा और अन्य धर्मिक व पर्यटन स्थलों की ओर बढ़ते यातायात को देखते हुए यह फैसला लंबे समय तक असर दिखाने वाला माना जा रहा है। इसी कड़ी में धमी सरकार ने सड़क, रोपवे और स्वास्थ्य से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को भी हरी झंडी दी है। मुख्यमंत्री ने राज्य में विभिन्न विकास योजनाओं के लिए कुल 183.97 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। इस राशि में मसूरी तथा रानीबाग (काठगोदाम) से नैनीताल मार्ग पर रोपवे निर्माण के फिजिबिलिटी अध्ययन के लिए 3.30 करोड़ रुपये शामिल हैं।

चार धाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों और स्थानीय लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा: पर्वतीय क्षेत्रों में रोपवे परियोजनाओं को सरकार भविष्य की परिवहन व्यवस्था के तौर पर देख रही है, क्योंकि इससे न केवल समय की बचत होती है, बल्कि सड़क यातायात का दबाव भी कम होता है। मसूरी और नैनीताल जैसे प्रमुख पर्यटन स्थलों पर रोपवे बनने से पर्यटकों को सुविध मिलने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा यमुनोत्री क्षेत्र में बड़कोट-पौंटी मोटर मार्ग के डामरीकरण और हेलीपैड की बाउंड्री निर्माण के लिए 1.89 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। चारधाम यात्रा के लिहाज से यह इलाका बेहद महत्वपूर्ण है और सड़क व हवाई सुविधाओं के सुदृढ़ होने से तीर्थयात्रियों के साथ-साथ स्थानीय लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार का जोर इस बात पर है कि चारधाम यात्रा मार्गों को हर मौसम में सुचारु और सुरक्षित बनाया जाए, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई संभव हो सके। हरिद्वार जिले में मंगलौर-रुड़की आवासीय परियोजना के अंतर्गत मार्ग निर्माण के लिए 2.49 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती आबादी और आवासीय जरूरतों को देखते हुए यह फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बेहतर सड़कें न केवल रहवासियों को सुविधा देंगी, बल्कि शहरी विकास को भी नई दिशा देंगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से धमी सरकार ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, रुद्रपुर के निर्माण कार्यों के एस्टीमेट के लिए 35 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की है। प्रदेश के तराई क्षेत्र में आधुनिक मेडिकल सुविधाओं के विस्तार की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। सरकार का मानना है कि मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों को मजबूत किए बिना आम लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराना संभव नहीं है। रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज के विकास से न केवल ऊधम सिंह नगर जिले बल्कि आसपास के क्षेत्रों के लोगों को भी लाभ मिलेगा और उन्हें बड़े शहरों की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ ही शहरी और सामाजिक सुविधओं के विस्तार पर भी सरकार ने ध्यान दिया है। नगर पंचायत गूलरभोज क्षेत्र के कोपा स्थित श्मशान घाट के निर्माण और नवीनीकरण के लिए 80 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। नगर निगम कोटद्वार क्षेत्र में एबीसी सेंटर के निर्माण के लिए 2.68 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं, जिससे आवारा पशुओं की समस्या के समाधान में मदद मिलने की उम्मीद है। क्लस्टर विद्यालय योजना के अंतर्गत देहरादून और टिहरी जिलों में चिह्नित तीन विद्यालयों के निर्माण कार्यों के लिए 5.46 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जो शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। धमी सरकार ने उत्तराखंड निवेश एवं आधरिक संरचना विकास बोर्ड के अंतर्गत शारदा घाट पुनर्विकास परियोजना के लिए 107.35 करोड़ रुपये की मंजूरी भी दी है। शारदा घाट क्षेत्र का पुनर्विकास धर्मिक, सांस्कृतिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि श्रद्धालुओं और पर्यटकों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

सुरक्षा और न्यायिक प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में भी सरकार ने कदम उठाया है। राज्य के सभी जनपदों में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय परिसरों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संसाधनों के माध्यम से साक्षियों की परीक्षा कराने के लिए 21 जनरेटर खरीदने हेतु 15.55 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। इससे न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने, साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और समय व संसाधनों की बचत में मदद मिलेगी। इसके अलावा ऊधम सिंह नगर जिले के खटीमा विधनसभा क्षेत्र में बिगराबाग से चकरपुर तक मार्ग को उच्चीकृत कर एक लेन से डेढ़ लेन किए जाने के लिए 9.45 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण इस मार्ग का सामरिक और आर्थिक महत्व भी बताया जा रहा है। सड़क चौड़ीकरण से स्थानीय लोगों के साथ-साथ सुरक्षा एजेंसियों को भी सुविध मिलेगी। इन सभी फैसलों के बीच राज्य राजमार्गों पर 235 पुलों के अपग्रेडेशन का निर्णय सबसे अहम माना जा रहा है, क्योंकि यह पूरे राज्य की सड़क व्यवस्था को नई मजबूती देगा। सरकार का कहना है कि पुलों की स्थिति का तकनीकी सर्वे कर उन्हें चरणबद्ध तरीके से आधुनिक बनाया जाएगा। जहां जरूरत होगी वहां चौड़ीकरण, भार क्षमता बढ़ाने और सुरक्षा उपायों को मजबूत किया जाएगा। इससे पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और आपदा के समय पुलों के क्षतिग्रस्त होने की आशंका को भी कम किया जा सकेगा। माना जा रहा है कि एक साथ सड़क, पुल, रोपवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और शहरी सुविधाओं पर निवेश से राज्य में विकास का संतुलित मॉडल सामने आएगा। धामी सरकार का यह विकास पैकेज उत्तराखंड को आने वाले वर्षों के लिए तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार ने यह स्पष्ट संकेत दिया है कि बुनियादी ढांचे को मजबूत किए बिना राज्य का समग्र विकास संभव नहीं है। सड़क और पुलों की मजबूती, रोपवे जैसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था, स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों का विस्तार तथा शहरी सुविधाओं का विकास ये सभी मिलकर उत्तराखंड की तस्वीर और तकदीर बदलने की दिशा में अहम साबित हो सकते हैं।

आईआईपी ने दुर्लभ प्रौद्योगिकी विकसित करके देश का नाम रोशन किया

भारतीय पैट्रोलियम संस्थान का देश के विकास में है विशेष योगदानः डॉ. हरेन्द्र सिंह बिष्ट

आईआईपी की एक प्रौद्योगिकी ने असम की जीडीपी में 0.1% बढ़ोत्तरी की

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) की स्थापना 1960 में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) की एक प्रयोगशालाओं में हुई थी। यह हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए समर्पित है। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) उत्तराखंड राज्य की राजधानी देहरादून में लगभग 250 एकड़ के परिसर में स्थित है। आईआईपी को वर्ष 1959 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। आईआईपी पेट्रोलियम शोधन और पेट्रोकेमिकल उद्योगों के लिए प्रक्रियाओं और उत्पादों का विकास, तेल और पेट्रोकेमिकल उद्योगों में कर्मियों का प्रशिक्षण, और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए मानक तैयार करने में सहायता करता है। संस्थान ने 1998 में आईएसओ 9001 प्रमाणन प्राप्त किया। संस्थान में 120 अनुसंधान एवं विकास वैज्ञानिकों की स्वीकृत अनुसंधान टीम है, जिन्हें 224 तकनीकी कर्मियों और 213 प्रशासनिक कर्मचारियों का सहयोग प्राप्त है। यह पायलट संयंत्रों सहित अत्याधुनिक अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं से सुसज्जित है। संस्थान का वार्षिक बजट लगभग 100 करोड़ रुपये है। संस्थान को 14 से अधिक विश्वविद्यालयों द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान करने वाले अनुसंधान हेतु मान्यता प्राप्त है। देश में तेल ईंधन की खोज और उसकी आपूर्ति सुनिश्चित कराने में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके साथ संस्थान के वैज्ञानिकों ने शोध के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। जिसमें प्लास्टिक तथा वेस्ट खाद्य तेलों से फ्यूल बनाने व जहाजों के लिए बायोफ्यूल बनाने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल हैं। पेश है भारतीय पैट्रोलियम संस्थान के निदेशक डॉ. हरेंद्र सिंह बिष्ट से हुई वार्ता के कुछ अंश.....

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) का भारत के विकास में क्या योगदान रहा है?

पिछले 65 वर्षों में आईआईपी ने कई ऐसी उपलब्धियाँ हासिल की हैं जो वैश्विक स्तर पर भी दुर्लभ हैं। भारत आज अमेरिका को पेट्रोल निर्यात करता है, लेकिन 2014 में अमेरिका ने अपने पेट्रोल में बेंजीन की मात्रा 0.62 प्रतिशत से कम रखने का नियम लागू किया। भारत के पेट्रोल में यह मात्रा लगभग 1% थी, जिससे निर्यात बंद होने का खतरा था। तभी आईआईपी ने बेहद कम समय में एक प्रौद्योगिकी विकसित की, जिसे रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अपनाया। इस प्रौद्योगिकी पर आधारित यह प्लांट 2016 से लगातार चल रहा है। इस प्रौद्योगिकी ने न केवल पेट्रोल को अमेरिकी मानकों के अनुरूप बनाया, बल्कि जो बेंजीन अशुद्धि के रूप में निकाला गया, वह पेट्रोल से भी महंगा उत्पाद निकला- यानी रिफाइनरी के लिए दोहरा लाभ। एक से डेढ़ साल में प्लांट की लागत भी पूरी वापस हो गई। इसी तरह असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के हैवी रेजिड्यू में पैराफिन वैक्स की मात्रा बहुत अधिक थी। आईआईपी, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड और नुमालीगढ़ रिफाइनरी ने मिलकर एक प्रौद्योगिकी विकसित की, जिससे देश में 50,000 टन प्रति वर्ष पैराफिन वैक्स उत्पादन का प्लांट लगा। पहले भारत पैराफिन वैक्स के 100% आयात पर निर्भर था, और आज 50% आयात बंद हो चुका है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी आज 41 देशों को वैक्स निर्यात कर रहा है। इस एक प्लांट ने असम की जीडीपी में 0.1% की वृद्धि की- यह आईआईपी का एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा, आईआईपी ने LPG की शुद्धता के लिए आवश्यक "THOXCAT-ES™" विकसित किया, जिसका उपयोग LPG में मौजूद सल्फर की अशुद्धि कम करने के लिए किया जाता है। यह कैटेलिस्ट आज भारत की 23 रिफाइनरियों में से 11 में चल रहा है, और दो विदेशी रिफाइनरियों, सऊदी अरामको और ORPIC ओमान में भी उपयोग में आ रहा है। जल्द ही यह संख्या 14 रिफाइनरियों तक पहुँचने की उम्मीद है। जिससे देश आयातित कैटेलिस्ट पर निर्भर नहीं रहेगा और पूरी तरह आत्मनिर्भर बन सकेगा। आईआईपी केवल बड़ी रिफाइनरियों के लिए ही नहीं, बल्कि छोटे किसानों और कारीगरों के लिए भी काम करता है। पारंपरिक गुड़ भट्टियों में बहुत धुआँ निकलता है और ईंधन की खपत भी अधिक है। आईआईपी ने इन भट्टियों का डिजाइन बदला, जिससे 15-20% दक्षता बढ़ी और धुआँ लगभग खत्म हो गया। आईआईपी ने अब तक उत्तराखंड और पश्चिमी उप्र में लगभग 67 भट्टियाँ सुधार दी गई हैं, और आने वाले समय में सभी पारंपरिक भट्टियों को धुआँ मुक्त बनाने का लक्ष्य है। इसी तरह ईंट भट्टों में आईआईपी ने 'हीट रिकवरी सिस्टम' विकसित किया, जिससे गर्म भट्टी की हवा को ठंडी भट्टी में भेजा जाता है और गर्म हवा को अगली भट्टी में उपयोग किया जाता है। इस प्रौद्योगिकी से एक भट्टा प्रति सीजन लगभग 7-8 लाख रुपये की बचत करता है। अब यह मॉडल शामली और उत्तराखंड के अन्य ईंट उद्योगों में भी लागू करने की योजना है। घरों में उपयोग होने वाले पीएनजी गैस बर्नर भी आईआईपी की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हैं। अक्सर एलपीजी चूल्हों के नोजल में छेद करके पीएनजी चूल्हे की तरह उपयोग किया जाता है, जिससे 20-25% ऊर्जा का नुकसान होता है। आईआईपी ने पीएनजी के लिए विशेष बर्नर विकसित किए, जो गैस की खपत 25-30% तक कम कर देते हैं। यह तकनीक अब पीएनजी रेगुलेटरी बोर्ड के साथ मिलकर अनिवार्य रूप दसे लागू कराने का प्रयास है। यह प्रौद्योगिकी लगभग 40 कंपनियों को ट्रांसफर की जा चुकी है। भारत का पहला सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) भी आईआईपी ने बनाया है। 2018 में देहरादून से दिल्ली तक स्पाइसजेट की पहली डेमो फ्लाइट आईआईपी के सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) पर उड़ाई गई। इसके बाद 2019 और 2024 की गणतंत्र दिवस परेड के फ्लाई-पोस्ट में भी आईआईपी के एसएएफ

का प्रयोग किया गया। यह ईंधन ''प्रयुक्त खाद्य तेलों'' यानी होटल व मंदिरों में जमा होने वाले बेकार तेल से बनाया जाता है। भारत में लगभग 3 मिलियन टन प्रयुक्त खाद्य तेलों का सालाना संभावित संग्रह है- और आईआईपी की प्रौद्योगिकी से इसे उच्च गुणवत्ता वाले विमान ईंधन में बदला जा सकता है। यह विश्व की सर्वश्रेष्ठ तकनीकों में से एक मानी जाती है। संक्षेप में, आईआईपी का योगदान बड़े औद्योगिक क्षेत्रों से लेकर छोटे किसानों और कारीगरों तक फैला हुआ है- रिफाइनरी प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण नियंत्रण, आत्मनिर्भरता, और पर्यावरण-अनुकूल ईंधन-हर क्षेत्र में आईआईपी ने देश को नई दिशा देने का काम किया है।

क्या कुकिंग ऑयल के अंदर भी कोई पेट्रोलियम पदार्थ होता है? और यदि हाँ, तो उसे विमान ईंधन (एविएशन फ्यूल) बनाने योग्य कैसे बनाया जाता है?

खाद्य तेलों में सीधे-सीधे पेट्रोलियम पदार्थ नहीं होते, लेकिन उसकी रासायनिक संरचना कुछ हद तक हाइड्रोकार्बन जैसी होती है। सामान्यत: कुकिंग ऑयल ट्राईग्लिसराइड होता है जिसमें ग्लिसरॉल के साथ तीन फैटी एसिड जुड़े होते हैं। जब हम इस संरचना को तोड़ते हैं, तो उसमें से जो लॉन्ग-चेन हाइड्रोकार्बन बनते हैं, वे रासायनिक रूप से पेट्रोल के हाइड्रोकार्बन से काफी मिलते-जुलते हैं। इन्हीं हाइड्रोकार्बन चेन को हम आगे मॉडिफाई करते हैं ताकि वे हवाई जहाज के ईंधन की अत्यंत कठोर क्वालिटी और सुरक्षा मानकों को पूरा कर सकें। विमान ईंधन के लिए थोड़ी भी खराबी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि हवा में गाड़ी की तरह रोककर चेक करने की सुविधा नहीं होती। इसलिए इसकी क्वालिटी कंट्रोल सबसे सख्त होती है। हमारा लक्ष्य यह होता है कि कुकिंग ऑयल से मिलने वाले हाइड्रोकार्बन को इतना परिष्कृत किया जाए कि वह बिल्कुल उसी एविएशन फ्यूल की स्पेसिफिकेशन को मैच करे जो अभी उपयोग में है। इस दिशा में भारतीय पेट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) काफी समय से अनुसंधान और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। इसी वैज्ञानिक प्रक्रिया से हमने कुकिंग ऑयल आधारित सुरक्षित एविएशन फ्यूल तैयार किया है।

आईआईपी का निदेशक नियुक्त होने के बाद आप अपने कार्यकाल की प्रमुख उपलब्धियाँ क्या मानते हैं?

निदेशक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद मेरी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल (एसएएफ) के 9000 टन प्रति वर्ष क्षमता वाले प्लांट की स्थापना है।

समृद्ध करियर के धनी हैं डॉ हरेन्द्र सिंह बिष्ट

उत्तराखंड की चाहत खींच लाई उनको आईआईपी में

भारतीय पैट्रोलियम संस्थान (आईआईपी) के निदेशक डॉ. हरेंद्र सिंह बिष्ट का जन्म 1971 में देहरादून में आईआईपी परिसर के नदजीक हरिपुर नवादा गाँव में हुआ। आपकी प्रारम्भिक शिक्षा आईआईपी परिसर के एक छोटे से प्राइमरी स्कूल में हुई। जूनियर हाई स्कूल तक आपने माजरी गाँव में पढ़ाई की और इंटरमीडिएट तक गुरु नानक पब्लिक बॉयज इंटर कॉलेज, खुरबुडा मौहल्ला से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की। इसके बाद आपने डीबीएस कॉलेज से केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी विषय के साथ बी.एस-सी. की तथा एसजीआरआर कॉलेज से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर्स किया। पढ़ाई के दौरान आपने आईआईपी में प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में काम शुरू किया और 1998 में वहीं से पॉलिमर साइंस में पीएचडी जॉइन की। पीएचडी पूरी करने के बाद आप दो साल के स्मार्ट पॉलीमर्स, जो तापमान या पी-एच बदलने पर अपनी संरचना बदलते हैं और कैंसर जैसी बीमारियों में टार्गेटेड ड्रग डिलीवरी के लिए उपयोग किए जाते हैं विषय पर पोस्ट-डॉक्टरेट के लिए अमेरिका गए। शोध पूरा करके भारत लौटने पर आपने एमिटी यूनिवर्सिटी में डेढ़ साल नैनो टेक्नोलॉजी विषय पर अध्यापन कार्य किया। इसके बाद आपने मुंबई की एक इंडस्ट्री में हाइड्रोकार्बन सेक्टर के लिए पॉलीमर ऐडिटिव्स पर काम किया। इसके बाद आप एक साल के लिए एमआरआई के लिए उपयोग होने वाले आयरन ऑक्साइड नैनोपार्टिकल्स पर पोस्ट डॉक्टरेट करने के लिए फ्रांस गए। 2009 में आपने भारत वापस रिलायंस इंडस्ट्रीज, जामनगर को ज्वाइन किया। यहां आपने लगभग 14.5 साल काम किया। यहाँ आपका कार्यक्षेत्र रिफाइनरी प्रक्रियाओं, हेवी रेजिडयू अपग्रेडेशन, डिलेड कोकिंग, उच्च-मूल्य वाले हाइड्रोकार्बन मॉलिक्यूल की रिकवरी तथा नीडल कोक जैसी उन्नत तकनीकों के विकास से जुड़ा रहा। इस प्रकार, आपकी विशेषज्ञता पॉलीमर साइंस, स्मार्ट पॉलीमर्स, नैनो टेक्नोलॉजी, मेडिकल नैनोमटेरियल, हाइड्रोकार्बन रिफाइनिंग तथा तकनीक विकास के विभिन्न क्षेत्रों में रही है। आपने 4 अगस्त 2023 को भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में निदेशक के रूप में ज्वाइन किया।

यह प्लांट एमआरपीएल, मंगलौर रिफाइनरी में लग रहा है, जिसका मैकेनिकल कम्प्लीशन सितंबर 2026 तक और प्रोडक्शन 2027 में शुरू होने की संभावना है। दूसरी बड़ी उपलब्धि पिरूल (पाइन नीडल) आधारित बायोजेनिक फ्यूल प्रोजेक्ट का तेजी से लागू होना है। यह प्रोजेक्ट उत्तराखंड में यूकॉस्ट के सहयोग से चल रहा है। पाइन नीडल गर्मियों में सूखकर जमीन पर गिरते हैं, उनमें रेजिन अधिक होता है और वे अत्यधिक ज्वलनशील होते हैं। जंगलों में लगने वाली अधिकांश आग का बड़ा कारण यही सामग्री है। हमने स्थानीय ग्रामीणों को पिरूल इकट्टा करने के लिए प्रेरित किया, जिसके बदले सरकार वर्तमान में ₹10 प्रति किलो तक भुगतान कर रही है। इस पहल से चंपावत जिले के भीमराड़ा क्षेत्र में 80-90 टन पिरूल इकट्टा किया गया, और जिस क्षेत्र में यह संग्रह हुआ वहाँ एक भी जंगल में आग नहीं लगी। जबकि आसपास के इलाकों में आग फैलती रही। पिरूल बहुत हल्का होने के कारण उसका ट्रांसपोर्टेशन बहुत महंगा पड़ता। एक ट्रक जिसमें 30 टन कोयला जा सकता है, उसमें केवल 3 टन पिरूल ही जा सकता है। इसे सुलझाने के लिए हमने वहीं

वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का संस्थान 'भारतीय पैट्रोलियम संस्थान'

बेंजीन निष्कर्षण प्लांट

ब्रिकेटिंग मशीन लगाई, जो पिरूल को दबाकर ठोस लकड़ी जैसे ब्रिकेट में बदल देती है। पिरूल में रेजिन पहले से होने के कारण कोई बाइंडर भी नहीं लगाना पड़ता। ब्रिकेट बनने के बाद हमने उसकी कैलोरीफिक वैल्यू जांची और उसे कोयले से तुलना की। यह सस्ता भी निकला और अधिक स्वच्छ भी। इसे हमने कोयला उपयोग करने वाले उद्योगों को सुझाया कि वहे प्रदूषण कम करने के लिए सस्ता बायोजेनिक ईंधन के रूप में पाइन नीडल से बने ब्रिकेट अपनाएँ। बायोजेनिक फ्यूल का लाभ यह है कि यह वातावरण में CO_2 की निश्चित मात्रा को नहीं बढ़ाता, क्योंकि पेड़ हवा से CO_2 लेकर बढ़ते हैं; इसे जलाने पर वही CO_2 वापस हवा में चली जाती है। जबकि कोयला, क्रूड ऑयल और गैस जैसे फॉसिल फ्यूल जलाने पर अतिरिक्त CO_2 वातावरण में जुड़ती है। इस प्रोजेक्ट को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्थानीय प्रशासन से भी अच्छा सहयोग मिला। मेरे आने के बाद यह पहल तेज गति से आगे बढ़ी और इसका स्पष्ट प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। इसके अलावा, संस्थान में चल रहे पुराने प्रोजेक्ट्स को भी मैंने फास्ट-ट्रैक मोड पर लाने का प्रयास किया है। इंडस्ट्री में मेरे लंबे अनुभव के कारण तेजी से काम करने की संस्कृति को मैं यहाँ भी लागू कर रहा हूँ, जिसके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो गए हैं। आने वाले समय में और भी बेहतर उपलब्धियाँ देखने को मिलेंगी।

उत्तराखंड में स्थित होने के कारण, आईआईपी उत्तराखंड के लिए कौन-कौन सी विशेष योजनाओं पर कार्य कर रहा है?

आईआईपी का वर्तमान में सबसे बड़ा फोकस उत्तराखंड को फॉरेस्ट फायर-फ्री बनाना है। इसके लिए पाइन नीडल ब्रिकेटिंग प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है। पिरूल (पाइन नीडल) से ब्रिकेट बनाकर न केवल पहाड़ों में लगने वाली आग को रोका जा सकता है, बल्कि ग्रामीणों की आय भी बढ़ाई जा सकती है और प्रदूषण भी कम होगा। उत्तराखंड में इस मॉडल के सफल होने के बाद अरुणाचल प्रदेश सहित अन्य राज्यों से भी अनुरोध आने लगे हैं, पर प्राथमिकता अभी उत्तराखंड ही है। इसके अलावा, आईआईपी एसडीसी फाउंडेशन के साथ मिलकर वेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट पर भी कार्य कर रहा है। राज्य के कई स्कूलों में "प्लास्टिक बैंक" बनाए गए हैं, जहाँ बच्चे प्लास्टिक लाकर जमा करते हैं। इस प्लास्टिक को आगे प्रौद्योगिकी के माध्यम से तेल में बदलने की दिशा में अनुसंधान चल रहा है। यह तकनीक फिलहाल लैब स्केल पर सफल हुई है, लेकिन बड़े स्तर पर लागू करने के लिए कुछ चुनौतियाँ हैं, जिन पर काम जारी है। तकनीक विकसित होते ही उत्तराखंड में इसके प्लांट लगाने की योजना है, जिससे प्लास्टिक प्रदूषण में कमी आएगी और स्थानीय लोगों को आय के अवसर भी मिलेंगे। स्टेट के लिए एक और महत्वपूर्ण दिशा रूम-टेम्परेचर बायोडीजल जैसी तकनीकों का स्थानीय स्तर पर उपयोग बढ़ाना है। चूँकि उत्तराखंड में कोई रिफाइनरी नहीं है, इसलिए परंपरागत रिफाइनिंग उपयोग यहां संभव नहीं है, लेकिन जहाँ भी गैस कनेक्शन जैसे हरिद्वार में पीएनजी उपलब्ध है, वहां ऊर्जा दक्षता से संबंधित तकनीकों के इंप्लीमेंटेशन पर कार्य किया जा रहा है।

कुल मिलाकर, आईआईपी का उद्देश्य है कि:

- पहले उत्तराखंड को प्राथमिकता दी जाए।
- पहाड़ों को आग से सुरक्षित किया जाए।
- प्लास्टिक वेस्ट को मूल्यवान संसाधन में बदला जाए।
- और स्थानीय लोगों की आय तथा पर्यावरण, दोनों में सुधार किया जाए।

आपके पिता आईआईपी में काम करते थे, आप यहीं पले-बढ़े और आपने आईआईपी को बहुत करीब से देखा। जब आप आईआईपी के निदेशक बने तो आपको कैसा महसूस हुआ?

जब मैं आईआईपी का निदेशक बना, तो मेरे अंदर भावनाएँ बहुत गहरी थीं। यह वही जगह है जहाँ मैंने अपना बचपन बिताया, अपनी पढ़ाई की और जिसने मुझे इतना सक्षम बनाया कि मैं विदेश जाकर रिसर्च कर सकूँ। इसलिए यहाँ वापस आकर नेतृत्व की भूमिका निभाना मेरे लिए बहुत सम्मान और गर्व का विषय था। हम गांव में रहते थे और बचपन में जब गांव से आईआईपी की ओर आते थे, तो हमें हमेशा लगता था कि आईआईपी के अंदर रहने वाले लोग किसी स्वर्ग में रहते हैं, न बिजली जाती, न पानी की दिक्कत, न कीचड़ वाली सड़कें। हम लोग मिट्टी की सड़कों से गुजरकर आते थे, पानी दूर से भरकर लाना पड़ता था, ट्रांसफॉर्मर खराब हो जाए तो हफ्तों बिजली नहीं आती थी। उस समय आईआईपी की लाइफ हमें बहुत अच्छी लगती थी। आज मेरे पास वही सुविधाएँ हैं, पर सच कहूँ तो मुझे गाँव की लाइफ ज्यादा प्यारी लगती है। गांव में इंसान बहुत कुछ सीखता है।

- कम में संतुष्ट होना,
- छोटी-छोटी चीजों में खुशी ढूँढना,
- न्यूनतम साधनों में जीवन जीना,
- और पर्यावरण को नुकसान न पहुँचाना।

ये सब बातें एक विकसित समाज में नहीं सीखाई जातीं। मेरी पत्नी भी गांव की है और हम दोनों आज भी उसी जीवनशैली को अपनाते हैं। हम अधिकतर पैदल चलते हैं, घर में न्यूनतम लाइट जलाते हैं, तापमान ठीक हो तो खिड़कियाँ खोलकर काम चलाते हैं। बहुत ठंड होने पर छोटा सा हीटर चलाते हैं, एसी का उपयोग लगभग नहीं करते। हम कोशिश करते हैं कि हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम से कम रहे। आईआईपी के निदेशक के रूप में काम करना मेरे लिए प्रोफेशनल उपलब्धि से ज्यादा एक भावनात्मक जुड़ाव है, क्योंकि मैंने

न सिर्फ इस संस्थान को बढ़ते हुए देखा है, बल्कि इसने मुझे जीवन में आगे बढ़ने की राह भी दी है।

विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड 2047 के लिए आप राज्य के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे?

मेरा सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि विकसित भारत किसी और ने नहीं बनाना है, हमें खुद बनाना है। अक्सर हम सोचते हैं कि "कोई दूसरा करेगा", लेकिन सच यही है कि विकास एक टीम वर्क है। इसमें देश का हर नागरिक, हर परिवार, हर युवा अपना योगदान दे। तभी 2047 का लक्ष्य पूरा होगा। विकसित होने की शुरुआत इंफ्रास्ट्रक्चर से नहीं, मानसिकता से होती है। हमारे देश का व्यक्ति जब किसी विकसित देश में जाता है, तो वह पूरी तरह विकसित नागरिक की तरह व्यवहार करता है। कचरा नहीं फैलाता नियमों का पालन करता है, पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का सही उपयोग करता है आदि। लेकिन जैसे ही वह अपने देश वापस आता है, उसकी वही मानसिकता गायब हो जाती है। यही सबसे बड़ी रुकावट है। अगर हम 2047 तक भारत और उत्तराखंड को विकसित देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हर व्यक्ति को अपने से यह पूछना होगा: "देश के विकास में मेरा योगदान क्या है?" जब हम सब मिलकर जिम्मेदारी निभाएँगे, तभी विकसित भारत और विकसित उत्तराखंड का सपना सच होगा।

आईआईटी रुड़की में हुआ "डिजाइन फॉर भारत यूथ इनोवेशन चैलेंज" प्रदर्शनी का आयोजन

• विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के अंतर्गत

• विकसित भारत/2047 के लिए डिजाइन-आधारित समाधानों के माध्यम से युवा नवोन्मेषकों को सशक्त बनाना

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 के अंतर्गत आयोजित "डिजाइन फॉर भारत–यूथ इनोवेशन चैलेंज" एक राष्ट्रीय स्तर की डिजाइन प्रतियोगिता है, जिसका उद्देश्य 18 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप नवाचारी डिजाइन समाधान विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। यह पहल युवा कार्य मंत्रालय तथा खेल एवं युवा कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई है। प्रतियोगिता भारत की सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक चुनौतियों से संबंधित डिजाइन हस्तक्षेपों पर केंद्रित है तथा सामाजिक प्रभाव और नवाचार को बढ़ावा देती है। यह पहल चार चरणों में संरचित है, जिसका समापन नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय प्रदर्शनी एवं पुरस्कार समारोह के साथ होगा।

इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, आईआईटी रुड़की द्वारा 16 दिसंबर 2025 को टिंकरिंग लैब, आईआईटी रुड़की में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से अनेक टीमों ने ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण किया, जिनमें से चयनित टीमों को प्रदर्शनी के दौरान अपने डिजाइन नवाचारों एवं रचनात्मक समाधानों को प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया। शीर्ष तीन टीमों का चयन राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा, जहाँ वे अपने नवाचारी प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगी।

प्रोफेसर इंदरदीप सिंह, अधिष्ठाता (अवसंरचना) एवं समन्वयक, डिजाइन इनोवेशन सेंटर, आईआईटी रुड़की, जिन्हें आईआईटी रुड़की के लिए प्रतियोगिता का नोडल अधिकारी नामित किया गया है, ने इस कार्यक्रम का सफल समन्वय किया।

इस अवसर पर प्रोफेसर नवीन कुमार नवानी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक कार्य), आईआईटी रुड़की, तथा प्रोफेसर विवेक कुमार मलिक, अधिष्ठाता (प्रायोजित अनुसंधान एवं औद्योगिक परामर्श), आईआईटी रुड़की, ने मुख्य अतिथि के रूप में सहभागिता की। अन्य विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर वरुण शर्मा, समन्वयक, टिंकरिंग लैब; प्रोफेसर सोनल अत्रेय एवं प्रोफेसर विभूति रंजन भट्टाचार्य, संकाय सदस्य, डिजाइन विभाग; डॉ. अजय डी. जैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, एसएमएयू हरिद्वार; श्री सुमित्रा पांडे, इंडस्ट्रियल रिसर्च कंसल्टेंट; तथा डॉ. नील मणि, निदेशक, सीएआई एवं आर, देव संस्कृति विश्वविद्यालय शामिल रहे। अतिथियों ने प्रतिभागियों से संवाद स्थापित किया तथा प्रदर्शित डिजाइनों की नवाचार क्षमता, रचनात्मकता एवं सामाजिक प्रासंगिकता की सराहना की।

देहरादून और मसूरी के 150 नागरिकों ने रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड को रोकने के लिए केंद्रीय मंत्री को लिखा पत्र

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से की प्रस्तावित परियोजना पर रोक लगाने की मांग

प्रस्तावित रिस्पना-बिंदाल एलिवेटेड रोड परियोजना को लेकर देहरादून और मसूरी के नागरिकों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। देहरादून सिटीजन्स फोरम और अन्य नागरिक समूहों से जुड़े 146 लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजकर इस परियोजना पर रोक लगाने की मांग की है। पत्र पर हस्ताक्षर करने वालों में देहरादून और मसूरी के विभिन्न वर्गों के लोग शामिल हैं, जिनमें पेशेवर, सेवानिवृत्त नागरिक, लेखक, शिक्षाविद, व्यापारी, सामाजिक व पर्यावरण कार्यकर्ता तथा आम नागरिक शामिल हैं।

नागरिकों ने पत्र में स्पष्ट किया है कि वे विकास के विरोधी नहीं हैं, लेकिन 21 गंभीर कारणों के चलते 26 किलोमीटर लंबी इस एलिवेटेड रोड परियोजना को देहरादून के लिए नुकसानदेह बताया है। उनका कहना है कि शहर पहले से ही अनियंत्रित शहरी विकास, स्थानीय ट्रैफिक जाम और बढ़ते पर्यावरणीय दबाव से जूझ रहा है। ऐसे में यह परियोजना समस्याओं का समाधान करने के बजाय पर्यावरणीय, भू-वैज्ञानिक, कानूनी, सामाजिक और आर्थिक जोखिमों को और बढ़ा देगी।

पत्र में कहा गया है कि देहरादून मेन बाउंड्री थ्रस्ट और हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट के बीच स्थित है, जो इसे भूकंपीय दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील बनाता है। पहले इस क्षेत्र को भूकंप जोन-4 में रखा गया था, लेकिन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा हाल ही में जारी भूकंप जोखिम मानचित्र में इसे जोन-6 में शामिल किया गया है। रिस्पना और बिंदाल नदियाँ रेत, बजरी और गाद की परतों से होकर बहती हैं, जो हल्के भूकंप के दौरान भी तरल की तरह व्यवहार कर सकती हैं। ऐसी स्थिति में एलिवेटेड रोड के खंभों के धंसने, झुकने या गिरने का गंभीर खतरा बना रहेगा। नागरिकों ने इस वर्ष 15 और 16 सितंबर को हुई तबाही का हवाला देते हुए कहा है कि इन नदियों में अचानक बाढ़ आती है। एलिवेटेड रोड का निर्माण नदियों के प्राकृतिक बहाव को बाधित करेगा, जिससे आईटी पार्क, डालनवाला, रेस कोर्स और इंदर रोड जैसे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। पत्र में यह भी कहा गया है कि नदी किनारे के क्षेत्र प्राकृतिक स्पंज की तरह भूजल को रिचार्ज करते हैं। जब इन्हें कंक्रीट से ढक दिया जाएगा, तो यह प्राकृतिक रिचार्ज प्रक्रिया बंद हो जाएगी।

पत्र में चेतावनी दी गई है कि यह परियोजना देहरादून को एक हीट आइलैंड में बदल सकती है और शहर की हवा की गुणवत्ता को भी खराब करेगी। इसका असर न सिर्फ शहरवासियों पर पड़ेगा, बल्कि रिस्पना और बिंदाल के किनारे रहने वाले छोटे-छोटे जीव-जंतुओं के अस्तित्व पर भी खतरा पैदा होगा। नागरिकों ने 2024 की भीषण गर्मी का उल्लेख करते हुए कहा है कि उस दौरान देहरादून का तापमान अप्रत्याशित रूप से 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। नागरिकों ने परियोजना से जुड़ी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर भी सवाल उठाए हैं। पत्र में कहा गया है कि अब तक न तो विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और न ही पर्यावरण प्रभाव आकलन सार्वजनिक किया गया है। परियोजना के नक्शे साझा नहीं किए गए हैं और यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितने लोगों को विस्थापित किया जाएगा। नागरिकों का कहना है कि इस निर्माण से देहरादून की स्काईलाइन स्थायी रूप से बदल जाएगी और शहर का प्राकृतिक स्वरूप भी प्रभावित होगा। पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि जनसुनवाई से जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। नियमों के अनुसार ऐसी सुनवाइयों की वीडियो रिकॉर्डिंग और लिखित दस्तावेज तैयार किए जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। नागरिकों का कहना है कि जब जनसुनवाई के दौरान आम लोगों ने अपनी बात रखने की कोशिश की, तो उनके साथ धक्का-मुक्की और हाथापाई तक की गई, जिसकी खबरें अखबारों में भी प्रकाशित हुई हैं। नागरिकों ने आशंका जताई है कि इस परियोजना से रिस्पना और बिंदाल नदियों के किनारे रहने वाले लगभग तीन हजार परिवार बेघर हो जाएंगे। ये परिवार दशकों से वहां रह रहे हैं और नियमित रूप से टैक्स, बिजली और पानी के बिल भी भरते हैं, इसके बावजूद उनके लिए कोई स्पष्ट पुनर्वास योजना सामने नहीं आई है। इसके साथ ही नदी किनारे छोटी दुकानें चलाने वाले लोगों और श्रमिकों का रोजगार भी खत्म होने की आशंका जताई गई है। पत्र में परियोजना की बढ़ती लागत पर भी गंभीर चिंता जताई गई है। नागरिकों का कहना है कि पिछले तीन वर्षों में परियोजना की लागत काम शुरू होने से पहले ही 4,500 करोड़ रुपये से बढ़कर 6,200 करोड़ रुपये हो चुकी है। उनका अनुमान है कि परियोजना पूरी होने तक यह लागत 8 से 10 हजार करोड़ रुपये या उससे भी अधिक हो सकती है, जो खराब योजना और आर्थिक प्रबंधन को दर्शाता है।

इसके विपरीत नागरिकों ने उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा तैयार कम्प्रिहेन्सिव मोबिलिटी प्लान-2024 का उल्लेख करते हुए कहा है कि उसमें इलेक्ट्रिक बसों, रोपवे, मौजूदा सड़कों के बेहतर उपयोग, पैदल-अनुकूल जोन और हरित परिवहन पर जोर दिया गया है। नागरिकों का मानना है कि यही दिशा देहरादून को अधिक सुरक्षित, हरित और स्मार्ट बना सकती है। पत्र में यह भी कहा गया है कि एलिवेटेड रोड से देहरादून के स्थानीय ट्रैफिक जाम की समस्या हल नहीं होगी। मसूरी डायवर्जन पर यह कॉरिडोर बॉटलनेक बन जाएगा और वहां भारी जाम लगेगा। शहर के घंटाघर, सचिवालय, दून अस्पताल और कचहरी जैसे प्रमुख क्षेत्रों में

जाने वाले लोगों को इससे कोई खास राहत नहीं मिलेगी। सहारनपुर चैक, बल्लीवाला, बल्लूपुर, दर्शन लाल चैक, सर्वे चैक और आराघर जैसे चौराहों पर ट्रैफिक की स्थिति जस की तस बनी रहेगी।

नागरिकों का कहना है कि देहरादून को एलिवेटेड रोड की नहीं, बल्कि एक ब्लू-ग्रीन कॉरिडोर की जरूरत है, जिसमें नदियों का संरक्षण, पैदल चलने के रास्ते, बस लेन, साइकिल ट्रैक और हरित पट्टियां विकसित की जाएं। पत्र के अंत में हस्ताक्षरकर्ताओं ने केंद्र सरकार से इस परियोजना पर पुनर्विचार करने और देहरादून के दीर्घकालिक हित में निर्णय लेने की अपील की है। इस पत्र पर जिन लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं, उनमें मुख्य रूप से देहरादून से अनूप नौटियाल, अनीश लाल, भारती जैन, जगमोहन मेहंदीरत्ता, रमना कुमार, रीतू चटर्जी, डॉ. उमेश कुमार, अजय दयाल, फ्लोरेंस पांधी, अभिनव थापर, डॉक्टर अरुणजीत धीर, किरण कपूर, राधा, मधुनजाली, अराधना नागरथ, राधेश लाल और मसूरी से गणेश सैली , कर्नल दास, हरदीप मान, मनमोहन कर्णवाल, प्रसेनजीत सिंह रॉय, तूलिका, रश्मि, शैलेन्द्र कर्णवाल, सुनील प्रकाश, अनिल प्रकाश, विनोद कुमार अग्रवाल, तान्या बक्शी, राहुल करनवाल आदि शामिल हैं। इनके साथ ही देहरादून और मसूरी के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों ने भी पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।

यूकॉस्ट में अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला सेवेरल कॉम्प्लेक्स वैरिएबल्स का सफल समापन

यूकॉस्ट एवं नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स के संयुक्त तत्वावधान में हुआ पाँच दिवसीय अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), देहरादून द्वारा नेशनल बोर्ड फॉर हायर मैथमेटिक्स के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित पाँच दिवसीय "अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला सेवेरल कॉम्प्लेक्स वैरिएबल्स" का दिनांक 19 दिसंबर, 2025 को सफल समापन हुआ। यह कार्यशाला दिनांक 15 से 19 दिसंबर, 2025 तक यूकॉस्ट में आयोजित की गई।

समापन समारोह के अवसर उत्तराखण्ड राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने वीडियो सन्देश के जरिये कार्यशाला में प्रतिभाग कर रहे सभी प्रतिभागियों को शुभकामनएं प्रेषित की।

सी०एम० धामी ने कहा कि गणितीय विश्लेषण के आधुनिक क्षेत्र पर केंद्रित इस कार्यशाला से देश और विदेश के अग्रणी शोधकर्ताओं तथा युवा वैज्ञानिको को आकादमिक संवाद का एक बेहतर अवसर प्राप्त हुआ होगा। उन्होंने कहा कि यह अंतराष्ट्रीय आयोजन उत्तराखण्ड के युवाओ को नयी दिशा देने के साथ साथ उत्तराखण्ड को एक उन्नत वैज्ञानिक अनुशंधान के एक प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने कि दिशा में यूकॉस्ट की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करेगा। उत्तराखण्ड की धरती में प्रतिभा कि कोई कमी नहीं है तथा यह कार्यशाला से राज्य में गणितीय शिक्षा के विकास में निर्णायक सिद्ध होगी और भविष्य में गणितीय प्रतिभाओ को मंच देने के लिए एक ठोस नीति बनाने में सहायक होगी।

समापन अवसर पर यूकॉस्ट के महानिदेशक प्रो. दुर्गेश पंत, ने कहा कि यह अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला न केवल उच्च स्तरीय अकादमिक विमर्श का सशक्त मंच बनी, बल्कि इसने युवा शोधकर्ताओं को वैश्विक विशेषज्ञों से सीधे संवाद एवं सीखने का अवसर भी प्रदान किया। उन्होंने कहा कि सेवेरल कॉम्प्लेक्स वैरिएबल्स जैसे उन्नत विषयों पर इस प्रकार के आयोजन उत्तराखंड को उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अनुसंधान और अकादमिक उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्रो. पंत ने कार्यशाला के सफल आयोजन हेतु सभी वक्ताओं, आयोजकों एवं प्रतिभागियों को बधाई दी। कार्यशाला के दौरान अंतरराष्ट्रीय स्तर के मिनी-कोर्स एवं आमंत्रित व्याख्यानों के माध्यम से सेवेरल कॉम्प्लेक्स वैरिएबल्स के सैद्धांतिक एवं अनुप्रयुक्त पहलुओं पर गहन चर्चा की गई। इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों एवं युवा शोधार्थियों के लिए एक विशेष सत्र का भी आयोजन किया गया, जिसमें डॉ. गोपाल दत्त द्वारा व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। इस सत्र के माध्यम से विद्यार्थियों को शोध की दिशा, समकालीन चुनौतियों तथा अंतरराष्ट्रीय अवसरों के संबंध में महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया गया, जिसे प्रतिभागियों द्वारा अत्यंत सराहा गया।

इस अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला का संयोजन डॉ. गोपाल दत्त (बी.बी.ए.यू., लखनऊ), डॉ. संजय कुमार पंत (दिल्ली विश्वविद्यालय), डॉ. विक्रमजीत सिंह चंदेल (आई.आई.टी. कानपुर) एवं डॉ. राजेंद्र सिंह राणा द्वारा किया गया। जापान, आयरलैंड, इटली, तुर्किये तथा भारत के विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों से आए विशेषज्ञों एवं शोधार्थियों की सहभागिता ने इस आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। कार्यशाला के आयोजन सचिव डॉ. राजेंद्र सिंह राणा ने बताया कि इस पाँच दिवसीय कार्यक्रम में देश एवं विदेश के प्रतिष्ठित संस्थानों से 60 से अधिक प्रतिभागियों ने सहभागिता की। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला ज्ञान-विनिमय, शोध सहयोग और दीर्घकालिक अकादमिक नेटवर्किंग की दृष्टि से अत्यंत सफल रही। समापन अवसर पर मुख्य रूप से यू कास्ट के संयुक्त निदेशक डॉ डीपी उनियाल, आई आई एस सी बैंगलोर के प्रोफेसर गौतम भराली, टोक्यो से प्रोफेसर याशुका तिब्बा, श्री दिनेश चंद्र अमित, श्री अमित पोखरियाल, डॉ पीयूष गोयल, डॉ ओमप्रकाश नौटियाल, डॉ भवतोष शर्मा, डॉ मंजू सुंदरियाल, श्री संतोष रावत, श्री रमेश रावत, श्री गजेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे।

उत्तराखंड में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए "बहु-अंग प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा विभाग" की स्थापना की जरूरत

सांसद नरेश बंसल ने राज्यसभा में उठाया मामला

डा. नरेश बंसल
भाजपा राष्ट्रीय सह कोषाध्यक्ष
व सांसद राज्यसभा

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि वर्तमान समय में अंग-विफलता एक सामान्य समस्या बनती जा रही है, तथा प्रत्यारोपण सेवाओं की माँग देश में उपलब्ध क्षमता से कहीं अधिक है।उत्तराखंड में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक "बहु-अंग प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा विभाग" की स्थापना की जाए।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के आँकड़ों के अनुसार, देश में प्रतिवर्ष 1.5 से 2 लाख गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, जबकि पिछले तीन वर्षों में पूरे देश में प्रतिवर्ष केवल 15 से 18 हजार प्रत्यारोपण ही हो पा रहे हैं। इसी प्रकार, देश को 50 हजार यकृत (लिवर) प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है, परंतु प्रतिवर्ष लगभग 4 हजार ही किए जा रहे हैं। अन्य अंगों के प्रत्यारोपण में भी यही स्थिति है। इन सभी आवश्यकताओं के बीच, उत्तराखंड भी इन सेवाओं से लगभग अछूता है।

डॉ. नरेश बंसल ने सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि यह सर्वविदित है कि भारत तेजी से डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है। अनियंत्रित मधुमेह के उपचार में कई बार पैनक्रियास प्रत्यारोपण ही अंतिम और प्रभावी विकल्प होता है। इसी प्रकार आंत्र (इंटेस्टाइनल) प्रत्यारोपण की भी बढ़ती आवश्यकता महसूस की जा रही है।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि हमारे देश में अंग दान की दर अत्यंत कम है-एक मिलियन जनसंख्या पर 1 से भी कम, और उत्तराखंड में यह दर लगभग नगण्य है। इसके विपरीत, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य देश में मृतक अंग दान के प्रमुख योगदानकर्ता हैं।

भाजपा राष्ट्रीय सहकोषाध्यक्ष एवं सांसद राज्यसभा डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, स्पेन अंग दान में विश्व में अग्रणी है। उसने वर्ष 2023 में 49.4 दाता प्रति मिलियन जनसंख्या तथा 2024 में 52.6 पीएमपी की दर प्राप्त की है। यह सफलता उनके अत्यंत सुविकसित "स्पेनिश मॉडल" के कारण संभव हुई है।

डॉ. नरेश बंसल ने सदन मे कहा कि इसलिए उत्तराखंड में बहु-अंग प्रत्यारोपण शल्य चिकित्सा विभाग की स्थापना न केवल अंग-विफलता से पीड़ित रोगियों के लिए आवश्यक है, बल्कि उन दाताओं और उनके परिजनों की सुरक्षा, सम्मान और गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिन्होंने निस्वार्थ प्रेम और स्नेह से अंग दान का महान कार्य किया है।

मुख्यमंत्री ने किया डॉक्यूमेंट्री 'द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू' उत्तराखंड के टीजर और पोस्टर का विमोचन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को निर्देशक ऋषभ कोहली और प्रशांत उपाध्याय के निर्देशन में परिवर्तन पिक्चर के बैनर तले बनी डॉक्यूमेंट्री 'द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू' उत्तराखंड के टीजर और पोस्टर का विमोचन किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि 'द ग्रेट हिमालयन रेस्क्यू' डॉक्यूमेंट्री में सामूहिक प्रयास और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत चित्रण है। उन्होंने कहा कि सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन उत्तराखंड के इतिहास में एक प्रेरणादायक अध्याय बन चुका है, जहाँ सभी एजेंसियों, प्रशासन और स्थानीय लोगों ने अभूतपूर्व समन्वय के साथ कार्य किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से लोग इस अभियान में तकनीकी दक्षता राज्य के जज्बे की झलक देखेगें। उन्होंने कहा कि यह फिल्म उत्तराखंड की 'संकल्प और सेवा' की भावना का प्रतीक है तथा युवा पीढ़ी को कठिन परिस्थितियों में धैर्य और कर्मनिष्ठा का संदेश देगी।

निर्देशक ऋषभ कोहली ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू ऑपरेशन पर आधारित है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इस ऐतिहासिक बचाव अभियान की कहानी को विस्तार से सुनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट्री न सिर्फ तकनीकी चुनौती और मानव जुझारूपन को दर्शाती है, बल्कि उत्तराखंड की जड़ों, भावनाओं और नेतृत्व की सच्ची तस्वीर भी पेश करती है, फिल्म की शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंट्री शीघ्र ही ओटीटी के बड़े प्लेटफार्म पर रिलीज होगी।

इस अवसर पर उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सीईओ बंशीधर तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार अनुपम त्रिवेदी, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन शादाब शम्स, फिल्म के निर्देशक, ऋषभ के पिता एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री नीरज कोहली मौजूद रहे।

ऊर्जा संरक्षण दिवस पर दून इंटरनेशनल स्कूल में हुआ पोस्टर मेकिंग कंपटीशन

भारतीय पेट्रोलियम संस्थान, सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर एवं दिव्य हिमगिरि के संयुक्त तत्वावधान में हुआ आयोजन

26 छात्रों को मिले आकर्षक पुरस्कार

दून इंटरनेशनल स्कूल सीनियर विंग में भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के 'जिज्ञासा' कार्यक्रम के अंतर्गत सीएसआईआर-भारतीय पेट्रोलियम संस्थान एवं सोसाइटी फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड अग्री के संयुक्त तत्वावधान में ऊर्जा संरक्षण पर एक पोस्टर मेकिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विभिन्न स्कूल्स के छात्र छात्राओं ने प्रतिभाग किया।

आयोजन में विभिन्न स्कूल्स के 26 छात्रों को आकर्षण इनाम के साथ मोमेंटो एवं अवॉर्ड सर्टिफिकेट प्रदान किए गए।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय पैट्रोलियम संस्थान के निदेशक डॉ हरेंद्र सिंह बिष्ट ने छात्रों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय पुरस्कार वितरण के बाद अपने ओजस्वी उद्बोधन में उपस्थित छात्र-छात्राओं की ऊर्जा के विभिन्न रूपों के बारे में समझाया और जीवन में ऊर्जा संरक्षण के महत्व को रेखांकित किया। कार्यक्रम का धन्यवाद ज्ञापन प्रधानाचार्य डॉ. दिनेश बर्थवाल द्वारा प्रेषित किया गया। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन के ज्यूरी सदस्य डीएवी कॉलेज के प्रो. हरिओम शंकर, एसजीआरआर यूनिवर्सिटी की डॉ नेहा सक्सेना एवं डीआईएस की सुश्री अनीता देवी ने विजेताओं के नाम घोषित किए। पोस्टर मेकिंग कंपटीशन में दो वर्गों में छात्रों ने भाग लिया, पहले वर्ग में कक्षा 6 से 8 के छात्र दूसरे वर्ग में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों ने प्रतिभाग किया। पुरस्कृत छात्रों की कृति को दून इंटरनेशनल स्कूल में आगामी होने वाली पीटीएम के दिन प्रदर्शित किया जाएगा।

कार्यक्रम का संचालन दून स्कूल समन्वयक सुश्री काजल क्षेत्री द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आयोजन सचिव डॉ. कुँवर राज अस्थाना, जिज्ञासा कार्यक्रम की समन्वयक डॉ आरती तथा टीम के सदस्य डॉ. ज्योति पोरवाल, डॉ. कमल कुमार, अंजलि भटनागर, सपना पैन्यूली, संजय कुमार, गोकुल कुमार व पंकज भास्कर उपस्थित थे।

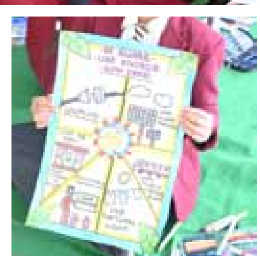

डॉ. संदीप सिंघल को दिया गया राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित "ऐमिनेंट इंजीनियरिंग पर्सनैलिटी" सम्मान

यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल को इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित "ऐमिनेंट इंजीनियरिंग पर्सनैलिटी" सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें 20 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में आयोजित 40वें इंडियन इंजीनियरिंग कांग्रेस के अवसर पर प्रदान किया गया। कार्यक्रम में डॉ. संदीप सिंघल के साथ ही इ.एम.इ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल आर.के. साहनी तथा किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डॉ. संजय किर्लोस्कर को भी सम्मानित किया गया।

डॉ. संदीप सिंघल सिविल इंजीनियरिंग में बी.ई., फाइनेंस में एम.बी.ए. तथा पावर मैनेजमेंट में पी.एच.डी. हैं। उन्हें जलविद्युत विकास के क्षेत्र में लगभग 38 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे यूजेवीएन लिमिटेड के साथ-साथ किशाऊ कॉर्पोरेशन लिमिटेड के भी प्रबंध निदेशक हैं तथा उत्तराखंड सरकार के ऊर्जा विभाग में ऊर्जा सैल के निदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे हैं।

उनके नेतृत्व में 120 मेगावाट व्यासी जलविद्युत परियोजना का सफल क्रियान्वयन हुआ है, वहीं 300 मेगावाट क्षमता की लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना एवं 660 मेगावाट की किशाऊ बहुउद्देशीय परियोजना जैसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। इसके अलावा वे पम्प्ड स्टोरेज, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन, हाइड्रोकाइनेटिक टरबाइन तथा भू-तापीय ऊर्जा जैसे नए ऊर्जा स्रोतों के विकास में भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

डॉ. सिंघल को इससे पूर्व भी राष्ट्रीय स्तर के कई प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें वाटर डाइजेस्ट वर्ल्ड वाटर अवार्ड, सी.बी.आई.पी. अवार्ड, ईटी इंस्पायरिंग लीडर्स अवार्ड तथा एक्वा फाउंडेशन डैम सेफ्टी अवार्ड शामिल हैं।

डॉ. संदीप सिंघल को राष्ट्रीय स्तर का प्रतिष्ठित ऐमिनेंट इंजीनियरिंग पर्सनैलिटी पुरस्कार मिलने पर यूजेवीएन लिमिटेड के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी गई।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया डॉ. दीपक कोहली की पुस्तक नई दुनिया नई तकनीक का विमोचन

योगी आदित्यनाथ, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, के कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास पर डॉ. दीपक कोहली, विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश सचिवालय ने अपनी नई पुस्तक, "नई दुनिया नई तकनीक'' मा. मुख्यमंत्री जी को भेंट की। इस अवसर पर डॉ. दीपक कोहली के सुपुत्र एवं प्रतिष्ठित कंपनी के साफ्टवेयर इंजीनियर श्री अभिनव कोहली भी उपस्थित रहे। यह पुस्तक समकालीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के आपसी संबंधों पर आधारित एक समग्र दृष्टि प्रस्तुत करती है, जिसमें डिजिटल ट्विन, क्वांटम तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वच्छ ऊर्जा, कृषि व रक्षा प्रौद्योगिकी जैसे विषय सम्मिलित हैं। डॉ. कोहली ने बताया कि उत्तर प्रदेश जिस प्रकार डिजिटल गवर्नेंस, आईटी सिटी विकास, स्टार्टअप संस्कृति, स्वच्छ ऊर्जा और तकनीक-आधारित विकास की दिशा में अग्रसर है, वही इस पुस्तक की मूल प्रेरणा है और यह पुस्तक युवाओं, शोधकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को वैज्ञानिक चेतना, नवाचार और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में विचारोत्तेजक दृष्टि प्रदान करेगी।

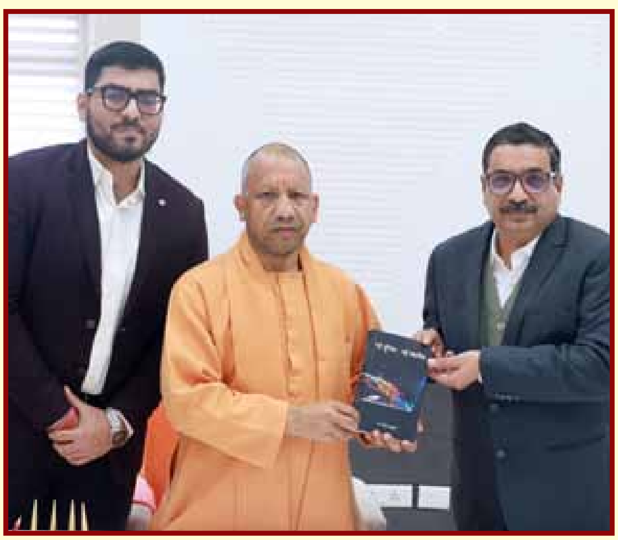

मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास की कसौटी पर जिलों की रैंकिंग की व्यवस्था शुरू

एस.डी.जी. के संकेतकों के आधार पर पहली बार जारी मासिक रैंकिंग में जनपद चम्पावत पहले स्थान पर

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य में सतत विकास लक्ष्य (एस.डी.जी.) के तहत चिन्हित विकास के लक्ष्यों के आधार पर जिलों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर मासिक रैंकिंग करने की व्यवस्था प्रारंभ की गई है। शुरूआती मासिक रैंकिंग में जनपद चम्पावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री द्वारा विकास के मोर्चे पर जिलों के प्रदर्शन के आकलन हेतु एस.डी.जी. के संकेतकों की कसौटी पर रैंकिंग करने की हिदायत दी गई थी। जिसके अनुपालन में नियोजन विभाग के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी एण्ड गुड गवर्नेस (सी.पी.पी.जी.जी.) द्वारा एस.डी.जी. की अवधारणा के अनुसार मासिक रूप से अनुश्रवण किए जाने योग्य चिन्हित संकेतकों की जनपदवार रैंकिंग शुरू की गई है। जिसके लिए सी.पी.पी.जी.जी. द्वारा इस वर्ष अप्रैल से अक्टूबर माह तक ११ सतत् विकास लक्ष्यों के कुल ३९ संकेतकों का डाटा प्राप्त करते हुए समसामयिक लक्ष्यों के आधार पर पहली बार जिलों की रैंकिंग जारी कर दी गई है।

मासिक रैंकिंग के आधार पर जनपद चम्पावत ने ९६ अंक प्राप्त कर प्रथम, जनपद बागेश्वर ने ९४ अंक प्राप्त कर द्वितीय तथा जनपद नैनीताल ने ९२ अंक प्राप्त कर तृतीय स्थान प्राप्त किया है। सी.पी.पी.जी.जी. के विशेष कार्याधिकारी अमित पुनेठा ने कहा है कि रैंकिंग में पिछड़े जनपदों से वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में सभी एस.डी.जी. में तय लक्ष्यों को प्राप्त कर करने की अपेक्षा की गई है। उन्होंने बताया कि रैंकिंग के लिए चिन्हित ३९ संकेतकों के अलावा आवश्यतानुसार समसामयिक लक्ष्यों के सापेक्ष योजनाओं का अनुश्रवण करने के लिए भविष्य में अन्य संकेतकों को भी शामिल किया जा सकता है।

एस.डी.जी. को लेकर उत्तराखंड में प्रतिबद्ध प्रयास: राष्ट्रीय स्तर पर बनी अलग पहचान

वर्ष 2030 तक गरीबी, भुखमरी, बीमारी और अभाव से मुक्त विश्व की परिकल्पना को साकार करने के उद्देश्य से सतत विकास लक्ष्य, संयुक्त राष्ट्र के १९३ सदस्य देशों द्वारा सितंबर २०१५ में स्वीकृत और अपनाए गए थे। एसडीजी के चार प्रमुख आयाम हैं : सामाजिक समानता; समावेशी आर्थिक विकास; पर्यावरण संरक्षण; और शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाज।

इन महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड राज्य में गंभीरता के साथ प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। जिसके फलस्वरूप उत्तराखंड विभिन्न विकास क्षेत्रों में अग्रणी बनकर उभरा है और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। नीति आयोग द्वारा जारी एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स वर्ष २०२३-२४ में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त कर सतत विकास के लिए प्रतिबद्ध प्रयासों की सार्थकता सिद्ध की है।

प्रदेश में सतत विकास के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने के लिए योजनाओं के बेहतर निर्माण के साथ ही उनके सफल क्रियान्वयन के लिए प्रभावी एक्शन प्लान बनाया गया है। इससे हम आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार के साथ राज्य के समग्र विकास की संकल्पना को साकार करने में भी सफल हो सकेंगे। इसी के दृष्टिगत सभी विभागों एवं जिलाधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुसार एस.डी.जी. के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने हेतु कार्य करने की अपेक्षा की गई है। जिलों की पहली रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहने वाले चंपावत जिले सहित अच्छा प्रदर्शन करने वाले अन्य जिलों को बधाई। सभी जिले बेहतर प्रदर्शन के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। जिन लक्ष्यों व इंडिकेटरों में हमें सुधार की आवश्यकता है, उन पर विशेष ध्यान दिया जाय।

-पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री

सतत विकास के चिन्हित लक्ष्य

एसडीजी सं. 1 गरीबी उन्मूलन
एसडीजी सं. 2 शून्य भुखमरी
एसडीजी सं. 3 उत्तम स्वास्थ्य
एसडीजी सं. 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
एसडीजी सं. 6 स्वच्छ पेयजल एवं स्वच्छता
एसडीजी सं. 7 संवहनीय स्वच्छ ऊर्जा
एसडीजी सं. 8 उत्तम कार्य एवं आर्थिक उन्नति
एसडीजी सं. 9 उद्योग, नवाचार एवं अवसंरचना विकास
एसडीजी सं. 10 असमानता दूर करना
एसडीजी सं. 11 संवहनीय शहर एवं समुदाय
एसडीजी सं. 15 भूमि पर जीवन

चार पीढ़ियों से दूनवासियों को क्वालिटी प्रोडेक्ट्स उपलब्ध करा रहा है प्लेनेट जेआर सुपरस्टोर

गौरव सिंघल

सन् 1947 में आटा चक्की के रूप में शुरू हुआ एक स्टोर आज देहरादून का एक नामी सुपरस्टोर ब्रांड प्लेनेट जेआर के रूप में स्थापित हो चुका है। यह सुपरस्टोर एक तरफ जहां प्रीमियम क्वालिटी प्रोडेक्टस उपलब्ध कराता है वहीं यहां का स्टाफ भी बहुत सपोंटिव नेचर का है जो कस्टमर की प्रोडेक्ट्स चुनने में उनकी भरपूर मद्द करता है। इस स्टोर को शुरू करने का विचार कैसे मन में आया और इसको यहां तक पहुंचने में किन-किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा है इसके लिए दिव्य हिमगिरी ने स्टोर के ओनर गौरव सिंघल से बातचीत की। पेश है बातचीत के कुछ अंश।

प्रश्न- आप अपने बारे में बताइए। इस बिजनेस में कैसे आना हुआ? अगर बिजनेस में नहीं आए होते तो क्या करियर चुनते?

उत्तर- मेरा नाम गौरव सिंघल है और मैं प्लेनेट जेआर स्टोर का ओनर हूँ। मेरा जन्म स्थान देहरादून है और मैने अपनी उच्च शिक्षा (पोस्ट ग्रेजुएट) यहीं से पूरी की है। सन् 1947 में हमारे परदादा और दादाजी ने मिलकर एक आटा चक्की शुरू की थी जिसको बाद में मेरे पिताजी ने संभाला और आटा चक्की के साथ-साथ एक प्रोविजन स्टोर भी शुरू किया। वर्ष 2000 में मैने अपनी 12 क्लास की पढ़ाई पूरी कर ली थी और दिल्ली जाकर चाटर्ड एकाउन्टेंट (सीए) की पढ़ाई करने की तैयारी शुरू कर दी थी। चूंकि उस समय काम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था इसिलिए अब मेरे पिताजी को भी सहायता की आवश्यकता महसूस होने लगी। उन्होंने मुझे अपने साथ दुकान पर बैठाना शुरू कर दिया। जैसे-जैसे दुकान पर मेरा समय बढ़ता गया, मेरी सीए की पढ़ाई पीछे होती गई। उस समय दुकान पर समय देकर मुझे अहसास हुआ कि हम अभी भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष ही कर रहे है और अगर मैं इस समय पिताजी को छोड़कर दिल्ली अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करने चला गया तो शायद हम पुरखों के खडे किये गये इस व्यवसाय में पिछड़ जायेंगे। यही सोचकर मैं इस बिजनेस की गहराई में उतरता गया और मुझे समझ आ गया कि ये बिजनेस ही मेरा करियर है और फिर मैं इसी को आगे बढ़ाने में लग गया। आज मैं अपने बिजनेस की ग्रोथ से पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे अपनी सीए की पढ़ाई पूरी नहीं करने का कोई मलाल दिल में नहीं है।

प्रश्न- यह स्टोर कब और किस सोच के साथ शुरू किया गया है और आप कौन सी पीढ़ी है?

उत्तर- सन् 1947 में हमारे परदादा और दादाजी ने एक आटा चक्की शुरू की थी जिसको मेरे पिताजी ने प्रोविजन स्टोर के साथ आगे बढाया। अपनी पढ़ाई के साथ-साथ मैने भी अपने पिताजी की सहायता करने के उददेश्य से दुकान पर समय देना शुरू कर दिया था। उस समय मेरी उम्र लगभग 22 साल थी और मैं अपने परिवार की चौथी पीढ़ी था। दो-तीन साल में ही मुझे अहसास हो गया कि अब हमें आटा चक्की के साथ ही और भी कुछ करना होगा। चूंकि उस समय ज्यादातर लोग हैल्थ को लेकर ज्यादा जागरूक नहीं थे। लोग सफेद आटा बिना चोकरवाला (जिसे मिल का आटा भी बोला जाता है) लेना पसंद करते थे, दालें पॉलिश वाली इस्तेमाल करते थे लेकिन लोगों की इस भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जो क्वालिटी पसंद थे। वे प्रोडेक्ट की पैकिंग पर नहीं बल्कि उसकी क्वालिटी पर ध्यान देते थे। हमने इन्हीं कुछ प्रतिशत लोगों को चिन्हित किया और वर्ष 2005 में हमने अपने इस प्रोविजन स्टोर को ही एक ऐसे स्टोर का रूप दिया जहां केवल उच्च क्वालिटी का नेचुरल और जैविक खाद्य उत्पाद ही उपलब्ध कराया जायेगा। आज घंटाघर से लेकर विकासनगर तक उच्च क्वालिटी के खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने वाला एकमात्र स्टोर प्लेनेट जेआर ही हैं। आज जब मैं पीछे मुडकर देखता हूँ तो गर्व करता हूँ कि जिस प्रोविजन स्टोर को मैने एक छोटा स्टोर बनाया

था आज वह सुपरस्टोर के रूप में एक भरा पूरा पेड़ बन चुका है।

प्रश्न- देहरादून के सभ्रांत परिवार आपके स्टोर को ही प्राथमिकता देते है इसकी क्या वजह है?

उत्तर- देहरादून के सभ्रांत परिवार जो अपने व परिवार के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, हमारे साथ इसिलिए जुडे हुए है क्योंकि जो उच्च क्वालिटी प्रोडेक्टस हमारे यहां होते है वे किसी के पास नहीं होते है। दरअसल हम सबसे सस्ता देने की होड़ में शामिल न होकर सबसे अच्छा देने की दौड़ में शामिल हुए। हमने अपने स्टोर में उन्हीं खाद्य उत्पादों को शामिल किया है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो। हम कभी क्वालिटी कम्प्रोमाइजर नहीं बने। मेरे पिताजी व दादाजी ने मुझको हमेशा सीख दी कि खाद्य उत्पादों में कभी मिलावट नहीं करनी है और ज्यादा पैसा कमाने के लालच में आकर बिना बिल का क्वालिटी कम्प्रोमाइज सस्ता सामान न ही अपने स्टोर में रखना है और न ही किसी ग्राहक को देना है। उनका हमेशा से ही यह मानना था कि खाद्य उत्पादों के बाजार में हमेशा क्वालिटी का ही राज होगा। आज क्वालिटी कंट्रोल हमारे हाथ में होने के कारण आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि कई सामान ऐसे है जो केवल हमारे यहां ही उपलब्ध होते है, जैसे हाई क्वालिटी का काजू, नेचुरल बिना पॉलिश की दाले जो हम सीधे किसानों से लेते है और उनको अपने यहां हैंडपिक (हाथों से सफाई) कराते है, देहरादून का फेमस बासमती चावल, चकराता का असली राजमा, सल्ट (अल्मोड़ा) की पहाड़ी हल्दी, बद्री गाय का घी, कोल्ड प्रेस्ड सरसो के तेल, देशी खांड, उच्च क्वालिटी की पहाड़ी हींग, हाई क्वालिटी का केसर इत्यादि। इसके अलावा हमारी अपनी एक आटा चक्की, जो क्लेमेनटाउंन एरिया में स्थापित है, वहां से चोकरवाले गेहूँ का आटा और मिलेटस आटे खुद से तैयार करवाते है और उसकी सिंपल पैकिंग करते है। हालांकि पहले भी और आज भी बाजार में कुछ लोग खाद्य उत्पादों के नाम पर सिर्फ बातें बेच रहे है लेकिन हमने शुरू से ही यह निश्चय किया था कि हम अपने ग्राहकों को अपने स्टोर के प्रोडेक्टस की क्वालिटी से कभी निराश नहीं करेंगे क्योंकि पैसे कमाने से ज्यादा लोगों का विश्वास कमाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। आज विकासनगर, पोंटा साहिब, राजपुर रोड, क्लेमेनटाउन सहित दूर-दूर से लोग हमारे स्टोर में खरीदारी करने आते है। हमारे ग्राहक खरीदारी करके जाते

समय जब हमसे कहते है कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे है और अपने उत्पादों की क्वालिटी को ऐसे ही बनाए रखना तो यही वो बात होती है जो हमको मोटिवेट करके रखती है।

प्रश्न- ब्लिकिंट, जेप्टो और इसी तरह के अन्य ऐप्स का क्या आपके स्टोर पर भी कोई प्रभाव हुआ है?

उत्तर- कोई विशेष प्रभाव नहीं पडा है क्योंकि जल्दी का कोई भी काम हो उसके रिजल्ट हमेशा ज्यादा अच्छे नहीं आते है। 10 मिनट डिलीवरी सिस्टम एक शार्टकट कॉन्सेप्ट हैं। इस तरह की सुविधा वाले ऐप्स आपको सस्ता और जल्दी सामान तो उपलब्ध करा सकते है लेकिन उत्पादों की क्या क्वालिटी होगी, वे कितने समय से वेयरहाउस में रखे होंगे इसकी कोई जानकारी वे अपने ग्राहकों को नहीं देते है। अगर मैं अपनी स्वंय की बात करूं तो खाद्य उत्पादों की क्वालिटी और उनके सोर्स को (कौन सा सामान कहां से और किस विश्वसनीय ब्रांड से लेना है) समझने में मेरी पीढ़िया लग गई। एक उदाहरण से समझाना चाहता हूँ कि जैसे हम 12 नंबर की काली मिर्च रखते है, खाद्य उत्पादों का व्यवसाय कर रहे कई लोगों को मसालों के नंबर तक की जानकारी भी नहीं होती है, आज बाजार में दालचीनी के नाम पर भी चायनीज कैसिया बेचा जा रहा है। इससे पूर्व भी सस्ते से सस्ता सामान देने की एक होड़ लगी थी और बिग बाजार तथा ईजी डे जैसे स्टोर ओपन हुए थे लेकिन आज वे स्टोर कहां है यह बताने की जरूरत नहीं है। खाद्य उत्पादों के इस बाजार में हमेशा से ही क्वालिटी का राज रहा है और आगे भी रहेगा। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ कि हमारे स्टोर पर इस तरह के ऐप्स का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है और हमारे ग्राहक स्टोर से ही अपने पूरे महीने की ग्रॉसरी और अन्य सामान लेकर संतुष्ट होकर जाते है।

प्रश्न- क्या आपने कभी प्लेनेट स्टोर की फ्रेनचाईजी देने पर भी विचार किया है?

उत्तर- नहीं, मैने कभी इस पर कोई विचार नहीं किया है। हालांकि मेरे पास कई प्रस्ताव आये और लोग अच्छी खासी रॉयल्टी भी देने को तैयार थे लेकिन मेरा मानना था कि अगर मैं इस चेन सिस्टम का हिस्सा बना तो अपनी क्वालिटी से हाथ धो बैठूंगा। आज इस स्टोर को मैं और मेरी पत्नी (नेहा सिंघल) मिलकर संभालते है और क्वालिटी कंट्रोल अपने हाथ में रखते है लेकिन अगर हमने इसकी कोई ब्रांच या फ्रेन्चाईजी शुरू की तो वहां की क्वालिटी पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होगा और अगर किसी ब्रांच की साख गिरेगी तो उसकी आंच हम तक भी आयेगी। इसलिए मैने कभी इस प्रस्ताव पर विचार ही नहीं किया।

प्रश्न- स्टोर को लेकर कोई फ्यूचर प्लान?

उत्तर- हमारे ग्राहकों की बढ़ती डिमांड के कारण अब हमारे यहां उत्पादों की संख्या बढ़ती जा रही है जिस कारण जगह की थोडी कमी हो गई है। अब हम शहर में एक बडी जगह सर्च कर रहे है जिसमें हम एक बड़ी पार्किंग की व्यवस्था की सुविधा देंगे ताकि हमारे ग्राहकों को किसी भी तरह की कोई असुविधा न हो और उन्हें खरीदारी करने का एक अच्छा अनुभव प्राप्त हो।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

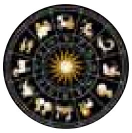
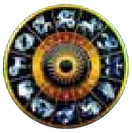
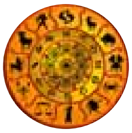

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- घर की देखरेख और सुख-सुविधाओं संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में परिवारजनों के साथ विचार-विमर्श होगा। कहीं से अच्छी तथा शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। किसी नजदीकी संबंधी की समस्या को हल करने में आपकी विशेष भूमिका रह सकती है। समझ और सतर्कता से अपने कार्यों में गति बढ़ाएं। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 7

वृषभ राशि- आप अपने दम पर हर काम को करने की क्षमता रखेंगे। अगर घर के रखरखाव संबंधी योजनाएं बन रही हैं, तो वास्तु सम्मत नियमों का भी पालन करना उचित रहेगा। अपने किसी खास हुनर को निखारने का प्रयास करेंगे। दिन के उत्तरार्ध में कुछ दिक्कतें रहेंगी। सावधानी बरतें और तनाव को हावी न होने दें। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 6

मिथुन राशि- कुछ महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बनेंगे, जो कि फायदेमंद साबित होंगे। घर के किसी सदस्य की उपलब्धि से खुशनुमा माहौल बनेगा। नजदीकी यात्रा भी संभव है जो कि लाभदायक भी रहेगी। बातचीत के दौरान नकारात्मक शब्दों के प्रयोग से बचें और अपने गुस्से पर काबू रखें। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 5

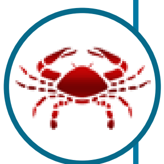

कर्क राशि- अपनी प्रतिभा और योग्यता को पहचानें। समय अनुकूल है, सिर्फ उसका सही सदुपयोग करने की जरूरत है। कुछ समय बागवानी करने और प्रकृति के सानिध्य में व्यतीत करने से मानसिक सुकून मिलेगा। किसी समारोह में जाने का भी निमंत्रण मिलेगा। अपने विचारों के साथ दूसरे लोगों के विचारों पर भी गौर करें। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 3

सिंह राशि- व्यस्ततम दिनचर्या में से कुछ समय अपने रुचि के कार्यों के लिए भी जरूर निकालें, इससे मानसिक सुकून मिलेगा। फोन कॉल के माध्यम से कोई महत्वपूर्ण सूचना मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों को शिक्षा व करियर से संबंधित समस्याओं का हल मिलेगा। पड़ोसी के साथ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 4

कन्या राशि- दिन की शुरुआत सुखद रहेगी। मेहनत के अनुरूप अच्छे परिणाम भी मिलेंगे। परिवारजनों के साथ घर में बदलाव तथा रखरखाव संबंधी कार्यों की भी योजनाएं बनेंगी। किसी मित्र अथवा संबंधी के साथ चल रही कोई भी समस्या सुलझाने का अनुकूल समय है। दिन के दूसरे पक्ष में सावधान रहने की भी जरूरत है। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 8

तुला राशि- घर के अनुभवी तथा वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद व सहयोग बना रहेगा। संपर्कों के माध्यम से नई-नई जानकारियां और संभावनाएं मिलेंगी। अपने मनपसंद और रुचि पूर्ण कार्यों में भी कुछ समय जरूर व्यतीत करें। इससे मानसिक सुकून बना रहेगा। मामा पक्ष के साथ संबंधों को मधुर बना कर रखना जरूरी है। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 2

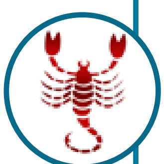

वृश्चिक राशि- पिछले कुछ समय से चल रही बाधाओं को दूर करने में सफल रहेंगे। जिससे आत्म संतुष्टि का भाव रहेगा। राजनीतिक व सामाजिक गतिविधियों में विशेष योगदान रहेगा। कार्यभार अधिक रहेगा, परंतु उसके परिणाम भी बेहतरीन ही मिलेंगे। जल्दबाजी और लापरवाही में कोई निर्णय लेना नुकसानदायक रहेगा। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 1

धनु राशि- अपने अधूरे पड़े कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करने में सक्षम रहेंगे। कुछ समय धार्मिक गतिविधियों के लिए भी जरूर निकालें, इससे मानसिक शांति बनी रहेगी। इस समय आपके विरोधी भी आपके व्यक्तित्व के सामने परास्त हो जाएंगे। अपनी कमजोरी को किसी के सामने भी जाहिर न करें। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 9

मकर राशि- घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग से कोई खास निर्णय लेने में सहजता महसूस करेंगे। बातचीत के माध्यम से किसी मसले का हल व समाधान मिल जाएगा। संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार मिल सकता है। अपने अंदर परिपक्वता लाएं तथा जल्दबाजी और भावुकता में कोई भी निर्णय न लें। भाग्यशाली रंग- ऑरेंज, भाग्यशाली अंक- 6

कुंभ राशि- दिन सुखद व्यतीत होगा। किसी धार्मिक गतिविधि में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा। तथा लोगों के बीच आपका विशेष रुतबा बना रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्यवाही हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें आने की आशंका है। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 6

मीन राशि- वरिष्ठ सदस्यों द्वारा आपको कोई बेहतरीन सलाह मिल सकती है। जिससे आप पूरे आत्मविश्वास और ऊर्जा के साथ किसी भी परिस्थिति का सामना करने में समर्थ रहेंगे। अपनी अन्य जिम्मेदारियों को भी आप बखूबी निभा लेंगे। किसी तरह का भी रिस्क लेने से आप नहीं डरेंगे। गैर कानूनी कार्यों से दूर रहें। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 8

कई गल्फ देशों में बैन होने के बाद भी धुरंधर ने बना दिया बड़ा रिकॉर्ड, पड़ोसी देश की उड़ी नींद

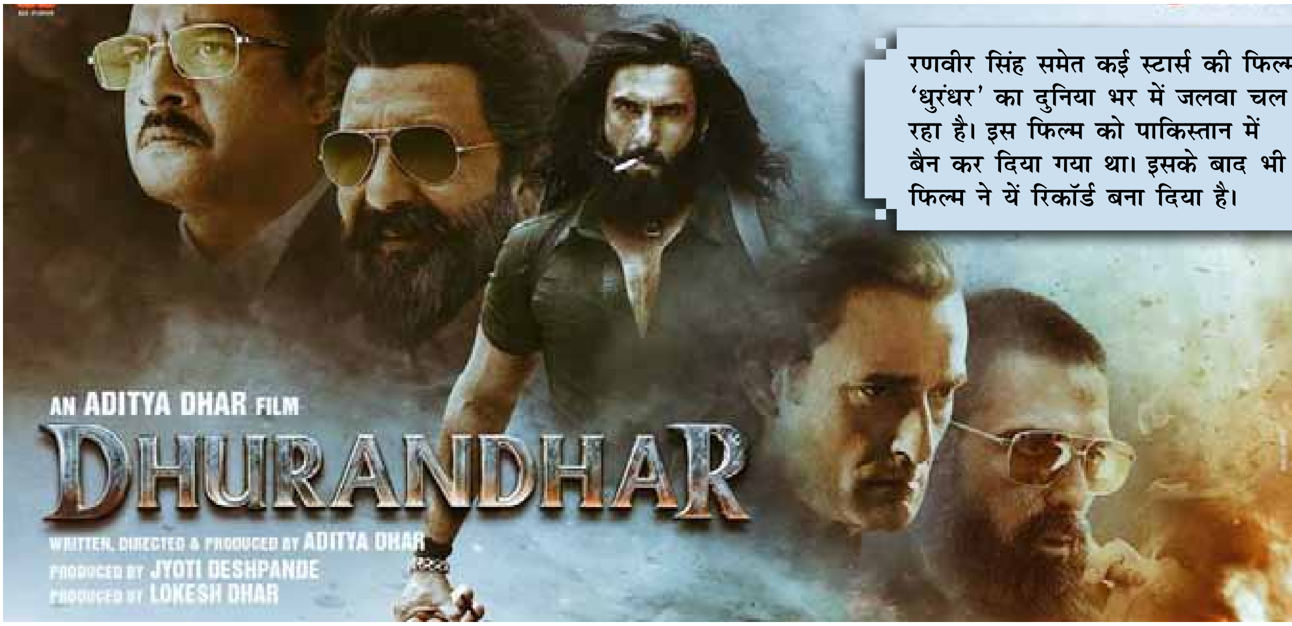

रणवीर सिंह समेत कई स्टार्स की फिल्म 'धुरंधर' का दुनिया भर में जलवा चल रहा है। इस फिल्म को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। इसके बाद भी फिल्म ने यें रिकॉर्ड बना दिया है।

बॉलीवुड फिल्म 'धुरंधर' इन दिनों देश और दुनिया भर में छाई है और लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिल्म के बारे में सिर्फ बातें नहीं हो रही हैं बल्कि लोग सिनेमाघरों में भी उमड़ रहे हैं और इसका अंदाज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से लगाया जा सकता है। फिल्म 'धुरंधर' ने संभवत: शुक्रवार को यानी 15वें दिन 500 करोड़ रुपये के क्लब में शामिल हो जाएगी। इसी बीच रणवीर सिंह की इस फिल्म ने पड़ोसी देश पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। फिल्म 'धुरंधर' ने पाकिस्तान में बैन होने के बाद बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है।

फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान में किया गया है बैन

फिल्म 'धुरंधर' को एंटी पाकिस्तानी कहते हुए वहां पर बैन कर दिया गया था। लेकिन फिल्म का क्रेज पड़ोसी देश के लोगों पर ऐसा चढ़ा कि उन्होंने इसकी पायरेसी शुरू कर दी है। अब हाल ऐसा हुआ है कि फिल्म 'धुरंधर' पाकिस्तान में मोस्ट पायरेटेड मूवी बन चुकी है. फिल्म 'धुरंधर' ने शाहरुख खान और रजनीकांत जैसे दिग्गज इंडियन स्टार्स की फिल्मों को पीछे कर दिया है।

पाकिस्तान के अलावा गल्फ देशों में बैन की गई फिल्म 'धुरंधर'

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' को काफी पसंद किया जा रहा है। इस फिल्म को पाकिस्तान में नहीं दिखाया जा रहा है। यहां तक कि पाकिस्तान में इस फिल्म को लेकर शिकायत भी दर्ज कराई गई। इसके साथ ही फिल्म को गल्फ के देशों में भी बैन कर दिया गया है। इन देशों का कहना है कि फिल्म 'धुरंधर' एंटी पाकिस्तान है।

पाकिस्तानियों पर चढ़ा है फिल्म 'धुरंधर' का खुमार

फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सामने आई 'आईएएनएस' की रिपोर्ट में बताया गया है कि पकिस्तान में 12 दिनों के अंदर फिल्म को 20 लाख से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। इस तरह से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पाकिस्तानियों पर भी फिल्म 'धुरंधर' का खुमार चढ़ा हुआ है।

पाकिस्तान में जमकर डाउनलोड की जा रही है फिल्म 'धुरंधर'

फिल्म 'धुरंधर' को श्रीलंका, नेपाल, मलेशिया के सर्वर का इस्तेमाल कर डाउनलोड किया जा रहा है। इसके बाद टेलीग्राम, अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स और वीपीएन के माध्यम से शेयर किया जा रहा है. फिल्म के लिंक कई पाइरेटेड साइट पर छाए हुए हैं। हालांकि, पाकिस्तानी खूफिया एजेंसी आईएसआई इस कोशिश में लगी है कि फिल्म 'धुरंधर' उनके देश तक ना पहुंच पाए।

फिल्म 'धुरंधर' के पाकिस्तान में बैन होने के बाद भी ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा है कि शाहरुख खान और रजनीकांत की फिल्मों के रिकॉर्ड टूट गए. शाहरुख खान की फिल्म 'रईस' और रजनीकांत की फिल्म '2.0' को काफी डाउनलोड किया गया था। अब फिल्म 'धुरंधर' ने पाइरेसी के मामले में दोनों फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।

फिल्म 'धुरंधर' में नजर आ रहे ये सितारे

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'धुरंधर' में रणवीर सिंह के अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, अक्षय खन्ना, आर. माधवन, सारा अर्जुन, राकेश बेदी जैसे स्टार्स नजर आ रहे हैं। फिल्म 'धुरंधर' सिनेमाघरों में 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी।

फिल्म 'धुरंधर' में दिखाया गया है कि पाकिस्तान में कराची के ल्यारी शहर में किस तरह से गैंग वॉर होता है। इसके अलावा फिल्म में देखने को मिलता है कि पाकिस्तान की खूफिया एजेंसी आईएसआई ने आतंकवादियों के साथ मिलकर भारत में आतंकी हमले करवाए थे।

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

Grace of the Himalayas

Pure, Natural & Rare

A2 Badri Cow Ghee

A2 Beta Protein

Bilona Method

Immunity Booster

fssai
22623030001586

UDYOG AADHAR MSME
UK050061483

THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS
Dalanwala, Dehradun
Customer Care - 7409782771

Available at

KUMAR SWEETS
Sahastradhara Road,
Near Crossing, Dehradun
7017180869

PLANET JR
Panditwadi,
Chakrata Road, Dehradun
9897477151